



सच समाचार

वर्ष-1 || अंक- 238 || पृष्ठ-8 || शुक्र- 2 र्पण || भोपाल || बुधवार 03 जून || 2026

सच-संक्षेप

बंगाल की खाड़ी में समुद्र के भीतर आया 4.6 तीव्रता का भूकंप

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। एनसीएस के मुताबिक, भूकंप 2 जून को सुबह 7:43:17 बजे आया। इसका केंद्र बंगाल की खाड़ी में 14.027 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 93.132 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गई, जिससे यह उथली श्रेणी का भूकंप माना जाता है।

सलमान खान ने काला हिरण के मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस

मुंबई। काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने मेकर्स के खिलाफ लीगल कार्यवाही की है। दबंग स्टार की टीम ने मेकर्स को एक नोटिस भेजा है, जिसमें इसकी रिलीज रोकने की मांग की गई है। इस पर प्रोड्यूसर अमित जानी की प्रतिक्रिया भी आई है। डीएसके लीगल ने एक्टर सलमान सलीम खान की तरफ से कास्टिंग डायरेक्टर अक्षय पांडे को एक लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें मांग की गई है कि काला हिरण नाम की एक फिल्म के डेबलपैमेंट और प्रमोशन को तुरंत रोक दिया जाए।

अजित अग्रवाल के वेदांता समूह पर ईडी की छापेमारी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को वेदांता समूह के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की। कारोबारी अजित अग्रवाल के वेदांता समूह पर ईडी ने फेमा उल्लंघन मामले में यह कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि वे तलाशी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन की जांच का हिस्सा है। मामले में अभी और जानकारी सामने आना बाकी है। कंपनी की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है।

सुप्रिया सुले के समधी को भाजपा ने दिया एमएलसी का टिकट

नागपुर। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए चंद्रपुर-वर्धा-गढ़चिरोली सीट से भाजपा उम्मीदवार और उद्योगपति अरुण लखानी ने कहा कि राजनीति और पारिवारिक रिश्ते अलग-अलग विषय हैं। दरअसल, लखानी के बेटे सागर लखानी का विवाह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती से 20 जून को होने वाला है। भाजपा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद एक मराठी समाचार चैनल से बातचीत में लखानी ने कहा, सुप्रिया ताई ने मुझे बधाई संदेश भेजा। पवार परिवार का जिज्ञा स्वाभाविक है क्योंकि वह एक बड़ा राजनीतिक परिवार है और हमारा उनसे पारिवारिक संबंध है। मुझे इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगता।

सरकार ने सीबीएसई से ओएसएम टैंडर रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली। सीबीएसई ने छात्रों की आंशरीय बदले जाने और कम नंबर के विवाद में एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने कोएम्प्ट को टैंडर देने को लेकर बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश का मन बना लिया है। हालांकि, सीबीएसई अधिकारियों ने गडबडी के आरोपों से इनकार किया और कहा है कि टैंडर सामान्य वित्तीय नियमों और सरकारी खरीद प्रक्रियाओं के अनुसार ही दिया गया था। सीबीएसई ने यह ठेका 5 दिसंबर को कोएम्प्ट एडुकेट को दिया गया था। यानी 17 फरवरी को पहली बोर्ड परीक्षा शुरू होने से ठीक 74 दिन पहले राहुल गांधी भी लगातार बोर्ड और शिक्षा मंत्री पर हमलावर हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने आरोप लगाया था कि ओएसएम के लिए टैंडर प्रक्रिया से किसी खास वेंडर को फायदा पहुंचाया गया। बोर्ड की रीवेन्यूएशन साइट सोमवार देर शाम तक नहीं खुल सकी। इससे लाखों छात्र परेशान हुए। बोर्ड की तरफ से दिनभर यही कहा गया कि 'पोर्टल विल गो लाइव सून'।

जोरदार धमाके के बाद गिरी बिल्डिंग, तीन लोग मलबे से निकाले

नई दिल्ली। दिल्ली के भलस्वा डेरी थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर इलाके में आज सुबह एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक जोरदार धमाके के बाद बिल्डिंग गिर गई। मलबे में कई लोग दब गए। जिनमें से तीन लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। एक व्यक्ति मलबे में दबा है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सिलिंडर ब्लास्ट के बाद इमारत गिरी है। दमकल विभाग की पांच गाड़ी मौके पर भेजी गई हैं। दमकल विभाग के मुताबिक, तड़के 9 बजकर 37 मिनट पर एक सेंटिध विस्फोट और उसके बाद मकान ढहने की सूचना मिली।

माहन कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम निर्णय

सच संवाददाता || भोपाल

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में लोकहित से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के पूर्व मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण होने, गेहूँ के रिकॉर्ड उत्पादन, उड़द और मूंग का पंजीयन आरंभ होने, प्रदेश में बड़े दुग्ध उत्पादन, धार भोजशाला, जल गंगा संरक्षण अभियान

आदि के संबंध में चर्चा की। दो सप्ताह बाद हुई कैबिनेट बैठक में आज खाद्य और सहकारिता विभाग के माध्यम से खरीदी केंद्रों में हुई गेहूँ खरीदी को लेकर भी सीएम डॉ मोहन यादव मंत्रियों के साथ चर्चा की जिसमें बताया गया कि देश में सबसे अधिक गेहूँ खरीदी का काम मध्यप्रदेश ने किया है। इसके साथ ही गोदाम में गेहूँ परिवहन और भंडारण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। बैठक में यूसीसी को लेकर भी चर्चा हुई और इसके लिए बनाई गई कमेटी द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी दी गई।



कई किलोमीटर दूर तक दिखाई लपटें मिवान स्टील प्लांट में लगी भीषण आग

रायपुर || एजेंसी

राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र स्थित मिवान स्टील लिमिटेड प्लांट में मंगलवार तड़के भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि उसकी ऊंची लपटें और धुएँ का घना गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। प्रातः जानकारी के अनुसार, आग मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे प्लांट परिसर में लगी। आग की सूचना मिलते ही फ़ायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ मौके पर रवाना की गईं। दमकल कर्मियों ने पहुंचते ही आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया, लेकिन आग की तीव्रता अधिक होने के



कारण इसे नियंत्रित करने में काफी मशकत करनी पड़ी। घंटों की कोशिश के बावजूद आग पूरी तरह काबू में नहीं आ सकी थी और दमकल विभाग की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रहीं। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गईं। हालात पर नजर रखने के लिए प्लांट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस हथ पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आग लगने के समय प्लांट में कितने कर्मचारी मौजूद थे।

जनगणना ने बढ़ाई टेंशन! यूपी, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में वक्त से पहले विधानसभा चुनाव की आहट

नई दिल्ली || एजेंसी

उत्तर प्रदेश और अगले वर्ष विधानसभा चुनाव वाले अन्य राज्यों में चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं। इसकी संभावनाओं को लेकर सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सूत्रों का कहना है कि आगामी जनगणना और उससे जुड़ी प्रशासनिक तैयारियों के कारण सरकारी मशीनरी पर बढ़ने वाले दबाव को देखते हुए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्णय या घोषणा नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में भी चुनाव कार्यक्रम और जनगणना संबंधी गतिविधियों के बीच तालमेल को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा चल रही है।

अधिकारियों और कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव
माना जा रहा है कि यदि दोनों प्रक्रियाएं एक ही समयवधि में संचालित होती हैं तो अधिकारियों और कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जिलाधिकारी स्तर से लेकर निचले स्तर तक बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी चुनाव और जनगणना दोनों प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनगणना के दौरान जिला प्रशासन को व्यापक स्तर पर संसाधन और मानवबल जुटाना पड़ता है, जबकि चुनाव के समय भी यही मशीनरी निरवचन प्रक्रिया का संचालन करती है।



राजनीतिक दलों में हलचल
समय से पहले चुनाव की चर्चाओं ने राजनीतिक दलों की गतिविधियों को भी तेज कर दिया है। भाजपा जहां पहले से संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय दिखाई दे रही है, वहीं विपक्षी दल भी संभावित चुनाव परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही अभी कोई आधिकारिक घोषणा न हुई हो, लेकिन चुनाव पूर्व तैयारियों के लिहाज से सभी दल सक्रिय नजर आ रहे हैं।

सातवें स्थान पर फिसला शेयर बाजार रैंकिंग में भारत को दोहरा झटका

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार के लिए वैश्विक मोर्चे से एक निराशाजनक खबर सामने आई है। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से भारत अब दुनिया के शीर्ष पांच शेयर बाजारों की सूची से बाहर हो गया है। महज एक हफ्ते के भीतर भारत को दो बड़े झटके लगे हैं। पहले ताइवान ने भारत को पछाड़कर पांचवां स्थान हासिल किया और अब दक्षिण कोरिया ने भी भारत को पीछे छोड़ दिया है। इस बदलाव के बाद भारत अब दुनिया का सातवां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि भारत की इस गिरावट और इन एशियाई देशों की शानदार बढ़त के पीछे असल कारण क्या हैं। ब्लूमबर्ग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में इस साल अभूतपूर्व तेजी देखने को मिली है। दक्षिण कोरिया की छलांग: इस साल दक्षिण कोरिया में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार मूल्य 86 प्रतिशत बढ़कर 5 ट्रिलियन (50 खरब) डॉलर तक पहुंच गया है। इस शानदार उछाल के साथ उसने कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख बाजारों को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत का नुकसान: इसके विपरीत, भारतीय शेयर बाजार का कुल मूल्यंकन खिसककर लगभग 4.8 ट्रिलियन डॉलर पर आ गया है, जिससे भारत ग्लोबल रैंकिंग में छठे से सातवें स्थान पर खिसक गया है।

गुजरात को शराबी बनाने के लिए तस्करी की राह खोलने के संजीव दुबे जबलपुर में अवैध शराब सिंडिकेट बनाने ठेकेदारों पर डाल रहे हैं दबाव !

सच संवाददाता || जबलपुर

प्रदेश में शराब का कारोबार नियमों के तहत और पूरी पारदर्शिता के साथ हो सके इसके लिए मोहन सरकार ने नई आबकारी नीति में ऐसे प्रावधान किए ताकि शराब सिंडिकेट न बन सके। बड़े समूहों का एकाधिकार खत्म करके छोटे-छोटे समूहों में दुकानें दी गईं ताकि नए लोग इस कारोबार में शामिल होकर स्वस्थ व्यवसायिक प्रतिस्पर्धी बनें। सरकार की मंशा साफ है कि लिंकर कारोबार पूरी तरह नियमों के अनुसार संचालित हो ताकि लोगों को गुणवत्तायुक्त शराब मिल सके लेकिन जबलपुर में सरकार की मंशा के उलट एक आबकारी अधिकारी खुद शराब सिंडिकेट बनवाने के लिए सक्रिय बताए जा रहे हैं। आमतौर पर सिंडिकेट शराब ठेकेदार मिलकर बनाते हैं लेकिन सूत्रों का कहना है कि जबलपुर में सिंडिकेट बनवाने में सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं



और इसके लिए ठेकेदारों पर दबाव बनाया जा रहा है। विदित है कि आबकारी अधिकारी संजीव दुबे पर धार में पोलिटिंग के दौरान महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात को शराबी बनाने के लिए तस्करी की राह खोलने के आरोप सर्वविदित रहे हैं। धार, झाबुआ और अलीराजपुर इंदौर संभाग में आते हैं जहां घपलों-घोटालों में दक्ष विनोद रघुवंशी सहायक आयुक्त रहें जबकि संजीव दुबे उपायुक्त थे। दागी अफसरों की इस जुगल जोड़ी ने इंदौर में पदस्थ रहने के दौरान खूब गुल खिलाए थे। लिंकर तस्करी रोकने का जिम्मा इंदौर संभाग के जिस उड़नदस्ते के पास था उसकी कमान दागी अफसर संजीव दुबे ही संभाले हुए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद दुबे को धार के उपायुक्त पद से हटाया गया था। उस समय एक आडियो खूब बायरल हुआ था जिसमें शराब तस्करी का पक्ष लेते हुए धार जिले के तत्कालीन विधायक

दागदार रहा है कार्यकाल

आबकारी अधिकारी संजीव दुबे का कार्यकाल विवादित और कार्यकाल दागदार रहा है। जहां-जहां पोलिटिंग हुई वहां-वहां उन पर शराब माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। इंदौर में पोलिटिंग के दौरान 42 करोड़ का र. फर्जी चलाना मामला उजागर हुआ था। ठेकेदारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर कई बार शिकायतें की जाती रही हैं। जबलपुर में शराब सिंडिकेट बनाने में उनकी विशेष दिलचस्पी से साफ है कि उच्चा स्तर पर प्रबंधन की कला में दक्ष श्री दुबे की कार्यशैली में इतना सख्त होने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया है।

राज्यवर्धन सिंह और डॉ हीरालाल अलावा के साथ प्रदेश के तत्कालीन वन मंत्री उमंग सिंघार पर शराब माफिया से लाखों रुपये लेन-देन का आरोप लगाया था। उस समय मंत्री तथा विधायकों की कड़ी आपत्ति के बाद उन्हें धार से तो हटा दिया गया था लेकिन अब जबलपुर में गुल खिला रहे हैं।

हर कार्यक्रम में राष्ट्रीय गाना वंदे मातरम लोगों के लिए बोझिल: थरूर

तिरुवनंतपुरम || एजेंसी

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत और अंत में राष्ट्रीय वंदे मातरम के सभी पांचों छंदों को बजाने या गाना अनिवार्य करने पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे गैर जरूरी और लोगों के लिए बोझिल बताया। केरल के तिरुवनंतपुरम में सोमवार को थरूर ने कहा, 96वें मातम हमारा राष्ट्रीय गाना है। जब इसे गाया जाता है, तो हम सम्मान में खड़े हो जाते हैं। इसका पहला छंद या पहले दो छंद ज्यादातर लोगों को जुबानी याद होते हैं। थरूर ने बताया कि पारंपरिक रूप से यह गीत किसी कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार गाया जाता था तो वहीं राष्ट्रगान अलग से कार्यक्रम के आखिर में बजाया जाता था। थरूर ने कहा- वंदे



मातरम सभी लोगों को याद नहीं। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में हुए एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए थरूर ने कहा कि वहां शुरुआत और अंत में वंदे मातरम का पूरा संस्करण बजाया गया। उनके मुताबिक, गीत लंबा होने के कारण लोगों के लिए दो बार खड़े रहना असुविधाजनक था। थरूर ने कहा आखिरकार इस मामले पर कोई फैसला लेना पड़ सकता है, क्योंकि संसद द्वारा पारित ऐसा कोई कानून नहीं है जो इसे अनिवार्य बनाता हो। मुझे राष्ट्रीय से कोई आपत्ति नहीं है।

फोन पर हुई तीखी बहस नेतन्याहू से भिड़े ट्रंप हुई तीखी बहस

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर गरमगरम बहस हुई। बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू पर जमकर निशाना साधा और इजरायली लीडर को अपने देश के प्रति दुनिया भर में दुश्मनी पैदा करने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। नेतन्याहू ने इजराइली हमले को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। ट्रंप ने आपा खोते हुए नेतन्याहू को जमकर फटकार लगाई और कहा कि तुम क्या कर रहे हो। यहां तक उन्हें पागल भी कह दिया। जानकारी के मुताबिक यह बहस उस समय हुई जब ईरान ने लेबानन पर इजराइली हमले को लेकर अमेरिका से शांति समझौते की बातचीत को छोड़ने की धमकी दी। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, ट्रंप ने इस बात पर निराशा जताई कि हिज्बुल्लाह के इजराइल पर हमलों के जवाब में मिलिट्री ने जोरदार जवाब दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक हिज्बुल्लाह कमांडर को टारगेट करने के लिए पूरी बिल्डिंग को नष्ट करने पर कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही बेरुत के खिलाफ तेल अवीव की बहती धमकियों पर भी सवाल उठाया। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू की बातचीत का मतलब है कि अब हर कोई आपसे नफरत करता है।



मौसम का मिजाज || मानसून की रफ्तार धीमी, जून भारत का अब तक का सबसे अप्रत्याशित महीना हो सकता है ग्रेट जून वेदर क्लैश, गर्मी से नहीं मिलेगी राहत !

नई दिल्ली || एजेंसी

भारत हाल के सालों में अपने सबसे अजीब और मुश्किल मौसम के दौर में जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस बार मॉनसून में सामान्य से कम बारिश, बहुत ज्यादा गर्मी, ज्यादा नमी, तेज आंधी और मॉनसून के आगे बढ़ने में देरी हो सकती है। भारत मौसम विभाग ने पहले ही जून के लिए सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने अपने सीजनल साउथवेस्ट मॉनसून के अनुमान को लॉन्ग पीरियड एवरेज के 90 प्रतिशत तक कम कर दिया है, जिससे प्रशांत महासागर में बन रहे एल नीनो के असर को लेकर चिंता बढ़ गई है। (साथ ही, मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉनसून के मौसम में बदलाव के दौरान देश के कुछ हिस्सों में खतरनाक नमी का स्तर, धूल भरी आंधी, बिजली और तेज आंधी आ सकती है।) मौसम की इन अजीब स्थितियों के कारण कुछ एक्सपर्ट्स ने इस स्थिति को 'ग्रेट



जून वेदर क्लैश' बताया है, जो भारत के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ होने वाली गर्मी, नमी और वायुमंडलीय अस्थिरता के बीच टकराव है। मॉनसून आ सकता है, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी हो सकती है। मौसम का अंदाजा लगाने वालों को चिंता में डालने वाली एक और बात अरब सागर के ऊपर वायुमंडलीय रुकावट की स्थिति की है। मौसम जानकारों का कहना है कि ऊपरी वायुमंडल में एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन (प्रतिचक्रवाती परिसंचरण) कभी-कभी मॉनसून के केरल पहुंचने के बाद भी मॉनसून की धाराओं की रफ्तार को धीमा कर सकता है।

गर्मी और नमी खतरनाक हालात पैदा कर सकती है हलांकि, पूरे उत्तर भारत में तापमान तुरंत रिकॉर्ड तोड़ने वाले स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। हलांकि, एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि नमी भी उतनी ही जरूरी वजह बन सकती है। मौसम के हिसाब से, 39 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान और बंगाल की खाड़ी से बढ़ती नमी मिलकर बहुत ज्यादा गर्मी का तनाव पैदा कर सकती है। ऐसे हालात में, महसूस होने वाला तापमान असल हवा के तापमान से काफी ज्यादा हो सकता है। भूयानिक विशेषज्ञ रजेश पौल ने कहा कि भारत में बहुत ज्यादा गर्मी आने वाली नमी के बीच एक बहुत कम होने वाला परस्पर क्रिया देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा, उत्तर भारत में बहुत ज्यादा गर्मी बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के साथ मिलकर खतरनाक नमी के स्तर और साथ ही तेज आंधी-तूफान पैदा कर रही है। हलांकि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, लेकिन कुछ इलाकों में महसूस होने वाला तापमान 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस बीच, कमजोर मानसून और एल नीनो की स्थिति को लेकर विचार पूरे देश में असमान बारिश और मौसम में उतार-चढ़ाव का खतरा बढ़ रही है। यह घटना उस चीज से जुड़ी है जिसे साइंटिस्ट वेद-बच इंफेक्ट कहते हैं, जिसमें ज्यादा नमी मौसम को ठीक से ग्राप बनने से रोकती है, जिससे इंसान के शरीर के लिए शुद्ध को ठंड करना मुश्किल हो जाता है। एक्सपर्ट्स ने बिना ज्यादा गर्मी के दलों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है।

मॉनसून का अनुमान कमजोर हुआ

आईएडी के नए लॉन्ग-रेंज अनुमान के मुताबिक, जून में बारिश सामान्य से कम रहने की उम्मीद है, जो महीने के औसत का 92 फीसदी से भी कम है। जून से सितंबर तक का मॉनसून सीजन भी सामान्य से कमजोर रहने की उम्मीद है, जिसमें पूरे भारत में बारिश लंबी अवधि के औसत का लगभग 90 फीसदी रहने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर पर एल नीनो की स्थिति बनने की बढ़ती संभावना है। पहले, एल नीनो की घटनाएं भारतीय मॉनसून सर्कुलेशन (भारतीय मानसून परिसंचरण) को कमजोर करती हैं और अबसर बारिश की कमी, बुवाई में देरी और गर्मी के बढ़ते तनाव से जुड़ी होती हैं। बलाइनेट मॉडल बताते हैं कि जून के दौरान कमजोर एल नीनो की स्थिति बन सकती है और जुलाई और अगस्त में धीरे-धीरे मजबूत हो सकती है।

आगरा में बारिश से सड़के धंसी, मकान ढहा

नई दिल्ली। देश के 23 राज्यों में जून की शुरुआत गर्मी से राहत लेकर आई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार के कई इलाकों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई। इससे तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में मंगलवार सुबह एक घंटा तेज हवा चली और बारिश हुई। इससे कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। कई जगह सड़कें धंस गईं। फुटपाथ धंसने से 25 फीट का गड्ढा बन गया। एक मकान का अगला हिस्सा गिर गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और बादल छाये से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में केरलम पहुंच सकता है। पहले 26 मई को मानसून पहुंचने का अनुमान लगाया गया था।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा

निजी अस्पतालों और संस्थाओं का भी लिया जाए सहयोग

लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई, बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहन करें : माहन



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक से अधिक जन भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। महिलाओं और बच्चों के कल्याण से संबंधित योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार हो। बच्चों और महिलाओं में पोषण स्तर को बेहतर करने के लिए संचालित गतिविधियों में स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित निजी अस्पतालों और संस्थाओं को भी जोड़ा जाए। इस दिशा में अन्य राज्यों और प्रदेश के जिलों में हो रहे सफल नवाचारों को अपनाने के लिए भी कार्यायोजना बनाई जाए। साथ ही मैदानी स्तर पर बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश सोमवार को मंत्रालय में हुई महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन औद्योगिक इकाइयों में महिला कर्मियों की संख्या अधिक है, उन इकाइयों में कामकाजी महिलाओं के लिए पीपीपी मोड पर हॉस्टल निर्माण की कार्ययोजना बनाई जाए। बैठक में बताया गया कि देवास, नर्मदापुरम, झाबुआ और सिंगरौली में बकिंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण प्रारंभ हो गया है। प्रताड़ित महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने के लिए पाहुण्डी, मऊजंग, मैहर, पेटलावद-झाबुआ, इंदौर के लसूड़िया और सावेर एवं धार के मनावर और पीथमपुर में वन स्टॉप सेन्टर स्वीकृत किए गए हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन अंतर्गत 51 जिला स्तरीय और 01 राज्य स्तरीय हेल्प सेंटर के माध्यम से 66 हजार से अधिक बच्चों को सहायता उपलब्ध कराई गई। जोरिमन ग्रस्त बच्चों की मैपिंग के लिए 13 जिलों में प्रक्रिया जारी है।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 5 से 6 आयु वर्ग के 9 लाख 28 हजार बच्चों के लिए विद्यार्थ आयोजित कर उन्हें विद्यार्थ प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया और बच्चों का शाला में सुगम

लाख से अधिक पात्र बहनों को 47 हजार 775 करोड़ रुपये से अधिक की मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मई 2026 तक 15 लाख 84 हजार बालिकाओं का पंजीयन कर 537 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की गई। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में दर्ज 15 लाख 51 हजार गर्भवती महिलाओं को 798 करोड़ 68 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। इस योजना के क्रियान्वयन में पिछले छह साल से मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को बीमा योजना से लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पोषण स्तर में सुधार के लिए किये जा रहे नवाचारों की जानकारी भी दी गई। बैठक में सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती जी.वी. रिसम सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में वरिष्ठजनों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की सुदृढ़ व्यवस्था

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को नई दिशा और गति प्रदान की गई है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित योजनाएं इसका प्रमाण हैं कि सरकार उनके सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा एवं अधिकारों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। बदलते सामाजिक परिवेश में जहां पारिवारिक संरचना में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, वहीं वरिष्ठजनों की देखभाल और उनके अधिकारों की रक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। इस दिशा में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। यह अधिनियम वरिष्ठजनों को

यह अधिकार देता है कि यदि वे स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हैं, तो वे अपने बच्चों या संबंधितों से भरण-पोषण प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय को भरण-पोषण अधिकरण तथा जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय को अपील अधिकरण घोषित किया गया है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय विभाग के जिला अधिकारियों को भरण-पोषण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से संचालित करते हैं। अधिनियम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा या परित्याग को दंडनीय अपराध माना गया है, जिससे समाज में उनके प्रति उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़

किया गया है। साथ ही, भरण-पोषण हेतु मासिक राशि निर्धारित करने का प्रावधान भी वरिष्ठजनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रय और देखभाल की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। विभिन्न संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के माध्यम से संचालित वरिष्ठ आश्रमों में जरूरतमंद वरिष्ठजनों को आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं एवं मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी कड़ी में भोपाल में विकसित संस्था छया वरिष्ठजन निवास एक महत्वपूर्ण पहल है। यह आधुनिक एवं सर्वसुविधायुक्त आवासीय परिसर वरिष्ठजनों को सुरक्षित, आरामदायक एवं गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करता है। यहां वातानुकूलित कक्ष, लाइब्रेरी, फिजियोथेरेपी, चिकित्सा सुविधाएं एवं मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए गए हैं।

खेत से ग्लोबल मार्केट तक, बोरगांव-शाहपुर फोरलेन से बदलेगी अर्थव्यवस्था, सब होगा सुपरफास्ट

सच संवाददाता ॥ आंकारेश्वर



महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा एनएच-753 एल का बोरगांव से शाहपुर खंड क्षेत्र के आर्थिक और परिवहन परिदृश्य को नई दिशा देने जा रहा है। आधुनिक चार-लेन राजमार्ग गलियारे के रूप में विकसित हो रही यह परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच संपर्क को मजबूत करने के साथ-साथ कृषि, व्यापार और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को भी गति प्रदान करेगी। विशेष रूप से बुरहानपुर के केला उत्पादकों को इस मार्ग से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वे अपनी उपज को तेजी से देश और विश्व बाजार तक पहुंचा सकेंगे। एनएच-753 एल का बोरगांव से शाहपुर तक का खंड रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह महाराष्ट्र के बोरगांव बुजुर्ग से मुकईनगर तक फैले एक बड़े सड़क गलियारे का हिस्सा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रहे इस कॉरिडोर से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच अंतर-राज्यीय संपर्क को नया स्वरूप मिलने की उम्मीद है। इससे न केवल परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। लंबी 944 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किया जा रहा यह सड़क गलियारा लगभग 47 किलोमीटर लंबा है। परियोजना का लगभग 85 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पूरी तरह तैयार होने के बाद यह मार्ग

इंदौर और छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) के बीच तेज, सुरक्षित और अधिक कुशल वैकल्पिक संपर्क मार्ग के रूप में उभरेगा। साथ ही यह क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत करते हुए अंतर-राज्यीय परिवहन की प्रमुख धुरी बनेगा। यह परियोजना केले, कपास, सोयाबीन और गेहूं जैसी फसलों के लिए प्रसिद्ध कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरती है। बेहतर सड़क संपर्क का सीधा लाभ किसानों और ट्रांसपोर्टर्स को मिलेगा। कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में कम समय लगेगा और परिवहन लागत में भी कमी आएगी। स्थानीय ग्रामीणों के लिए भी यह राजमार्ग दैनिक जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। नए मार्ग के बनने से ट्रकों की आवाजाही अधिक सुगम हो गई है, जिससे कृषि उपज का परिवहन रहने की तुलना में अधिक कुशल और तेज हो सकेगा। इस गलियारे में 1 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 20 छोटे पुल, 98 पुलिया, 3 हल्के वाहनों के लिए अंडरपास और 6 वाहनों के लिए अंडरपास शामिल हैं। इन संरचनाओं को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि स्थानीय

संपर्क प्रभावित न हो और गांवों, खेतों तथा आसपास के क्षेत्रों के बीच आवागमन सुचारु एवं निर्बाध बना रहे।

तेजी से चल रहा है निर्माण कार्य

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के प्रोजेक्ट मैनेजर आशुतोष सोनी ने बताया कि खंडवा से आगे बोरगांव-शाहपुर तक 47 किलोमीटर लंबे हिस्से का लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। वहीं संपूर्ण 204 किलोमीटर सड़क परियोजना का निर्माण कार्य भी तेज गति से जारी है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण पूरा होने के बाद इसे जल्द ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इंदौर-खंडवा-इच्छापुर सड़क मार्ग की कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना के लिए 8,600 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस परियोजना का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य इंदौर के समीप शिमरोल, चोरल और बलवाड़ा क्षेत्र में पहाड़ों को काटकर तथाल सड़क मार्ग का निर्माण तथा

परियोजना एक नजर में

- ◆ परियोजना: एनएच-753 एल बोरगांव-शाहपुर खंड
- ◆ परियोजना लागत: 944 करोड़ रुपये
- ◆ कुल लंबाई: लगभग 47 किलोमीटर
- ◆ जुड़ने वाले प्रमुख राज्य: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र
- ◆ प्रमुख संपर्क मार्ग: इंदौर-खंडवा-बुरहानपुर-जलागाँव-छत्रपति संभाजीनगर
- ◆ प्रमुख अवसंरचना: 1 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 20 छोटे पुल, 98 पुलिया और 14 अंडरपास
- ◆ बाईपास: शहरी क्षेत्रों में भीड़ कम करने के लिए लगभग 26 किलोमीटर लंबा बाईपास
- ◆ सर्विस रोड: सुरक्षित स्थानीय आवागमन के लिए 19 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड
- ◆ विशेषता: तेज और सुरक्षित यातायात को ध्यान में रखकर

आंकारेश्वर के समीप मोरटक्का में नर्मदा नदी पर छह लेन पुल का निर्माण था। ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य अब पूर्ण हो चुके हैं।

उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सफर होगा आसान

सड़क परियोजना के पूर्ण होने के बाद उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले वाहनों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे यात्रा का समय कम होगा, ईंधन की बचत होगी और माल परिवहन अधिक तेज और सुरक्षित हो सकेगा। भारतमाला परियोजना के तहत विकसित हो रहा यह आधुनिक राजमार्ग आने वाले समय में क्षेत्र के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बनने जा रहा है।

रीवा में सरकारी गाड़ी से बकरियां चोरी, आधी रात गांव में मचा कोहराम

रीवा। गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम पोखरा से बकरी चोरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि

रीवा के संजय गांधी अस्पताल के शासकीय शव वाहन के चालक राजेश मिश्रा ने बकरी चोरी की है। इसकी सूचना जब पुलिस को दी गई, तो पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 6 बकरियां भी बरामद की गई हैं। इसके साथ ही शासकीय शव वाहन को भी जब्त किया गया है। 28 मई को बकरी चोरी होने की शिकायत फरियादी के द्वारा गुड़ थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करते हुए बकरी चोर की तलाश शुरू कर दी थी।

पुलिस जब पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के लिए पोखरा गांव पहुंची, तो ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी गई की देर रात परिवार के सदस्य घर के अंदर सो रहे थे, जबकि बकरियां घर के बाहर बंधी हुई थीं। रात में शव वाहन लेकर पहुंचे लोगों ने बकरियों को वाहन में भर लिया और मौके से भागने लगे। इसी दरमियान आहत सुनकर परिवार के सदस्य जाग गए और काफी दूर तक शव वाहन का पीछा भी किया। लेकिन वह बकरियां समेत शव वाहन लेकर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक फरियादी ने बताया था कि एम्बुलेंस की तरह दिखाई देने वाले एक शव वाहन गांव में दिखाई दिया था। पुलिस की टीम ने जब गहनता से पड़ताल की, तब शव वाहन के चालक राजेश मिश्रा का नाम सामने आया। जिसके बाद पुलिस की टीम ने राजेश मिश्रा सहित उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया है।

बुंदलेखंड बदनाम, परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट प्रदेश में बड़े बाल विवाह के मामले

सच संवाददाता ॥ भोपाल



हाल ही में मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से बाल विवाह का चौंकाते वाला मामला सामने आया था, यहां दूल्हा 42 साल का था जबकि दुल्हन उम्र में तीन गुना छोटी यानी सिर्फ 13 साल की बच्ची थी। इस घटना ने प्रदेश में हो रहे बाल विवाह के मामलों को उजागर कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक प्रदेश में 20 फीसदी ऐसे मामले पाए गए हैं, जहां लड़की की शादी 18 साल के पहले ही कर दी गई। बच्चों को लेकर स्वयं सेवी संस्था संचालित डॉ अर्चना सहाय कहती हैं, इंदौर में हुई घटना प्रदेश की कोई पहली घटना नहीं है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इसके कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। राजगढ़ क्षेत्र में कम उम्र में विवाह करना परंपरा है, इसे काफी कोशिश के बाद भी खत्म नहीं किया जा सका, लेकिन बुंदेलखंड के दमोह, सागर, छतरपुर, गुना, मुरैना आदि क्षेत्रों में इसके कई दूसरे सामाजिक कारण हैं। बच्ची के 16 साल तक पहुंचने तक लगभग उनका पढ़ना-लिखना बंद हो जाता है और ऐसे में परिवार बच्ची की शादी की कोशिशें शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बच्ची को कोई गलत रास्ते पर न ले जाए। डॉ अर्चना सहाय आगे कहती हैं, ऐसा नहीं है कि गांवों में ही ऐसी स्थिति है, शहरों में भी बाल विवाह के मामले सामने आ रहे हैं। टीकमगढ़ जिले की मोहरगढ़

तहसील के लाखन केवट (बदला हुआ नाम) ने भी अपनी बेटी का विवाह 18 साल के पहले ही कर दिया। वे कहते हैं कि पहले सोचा था कि बेटी के बालिंग होने के बाद ही उसके ब्याह करेंगे, लेकिन उसका भी समाज की एक लड़की कहीं चली गई, तो घटना के बाद बेटी की पिछले साल शादी कर दी।

बाल विवाह के आंकड़ों में अंतर

प्रदेश में बाल विवाह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर आंकड़ों की अपनी अलग कहानी है। बाल विवाह को लेकर लोकसभा और मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को लेकर भी काफी अंतर है। 2025 में लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों को देखें तो मध्यप्रदेश में 2018 से 2022 के दौरान कुल 23 बाल विवाह के मामले सामने आए हैं। साल 2022 में प्रदेश में सिर्फ 7 मामले सामने आए। इन मामलों में पीसीएमए 2006 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। हालांकि, मध्यप्रदेश विधानसभा के आंकड़े इनसे कई

गुना ज्यादा हैं।

2025 में हुए 538 बाल विवाह

सरकार द्वारा विधानसभा में हाल ही में आंकड़े प्रस्तुत किए गए। यह आंकड़े चौंकाते वाले हैं। साल 2025 में प्रदेश में 538 बाल विवाह के मामले सामने आए हैं। पिछले सालों के मुकाबले प्रदेश में बाल विवाह के मामले घटने के स्थान पर लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2020 में प्रदेश में 366 बाल विवाह के मामले सामने आए थे, जो हर साल लगातार बढ़ते गए। 2025 में बाल विवाह के सबसे ज्यादा मामले दमोह जिले में सामने आए हैं। दमोह में 115 बाल विवाह के मामले सामने आए हैं।

- ◆ साल 2020 में प्रदेश में 366 बाल विवाह के मामले आए
- ◆ साल 2021 में 436 बाल विवाह के मामले सामने आए
- ◆ साल 2022 में 519 बाल विवाह के मामले सामने आए
- ◆ साल 2023 में 528 बाल विवाह के मामले सामने आए
- ◆ साल 2024 में 529 बाल विवाह के मामले सामने आए
- ◆ साल 2025 में 538 बाल विवाह के मामले सामने आए

बोरिया बिस्तर ले इंदौर में जमे 44 गांवों के किसान, मध्य प्रदेश में दिल्ली जैसा किसान आंदोलन

सच संवाददाता ॥ इंदौर

इंदौर में प्रस्तावित रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। सैकड़ों किसान इंदौर कलेक्टर कार्यालय चौराहे पर धरने पर बैठ गए हैं। वे अपने साथ दरी-चादर और गद्दे लाए हैं। इसके अलावा खाना बनाने का इंतजाम भी किया है। किसानों की मांग है कि रिंग रोड बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण कैबिनेट किया जाए। जब तक मांग नहीं मानी जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय चौराहे पर धरने पर सैकड़ों किसान धरने पर बैककर नारेबाजी करने लगे। किसानों का कहना है कि शिप्रा से लेकर पीथमपुर तक रिंग रोड नहीं बनने दी जाएगी। जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उन्हें नाममात्र का मुआवजा दिया

जा रहा है। किसान कई दिनों से इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों ने मांग है कि पूर्वी रिंग रोड और मनमाड रेलवे लाइन योजनाओं को निरस्त किया जाए। इन दोनों योजनाओं से 44 गांवों के किसान किसान प्रभावित हो रहे हैं। 2500 किसान इस योजना से बर्बाद हो जाएंगे। किसानों का कहना है कि यह प्रदर्शन आने वाले दिनों उग्र भी हो सकता है, यदि सरकार ने इस को लेकर योजनाओं में बदलाव नहीं किए तो हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। पिछली बार भी हमने प्रदर्शन किया था, उस दौरान आश्वासन मिला था कि योजना में जल्दी बदलाव किया जाएगा। लेकिन अभी तक हमें भी किसी तरह का कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। किसान संतोष सोनकिया का कहना है मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

तो क्या ग्वालियर-चंबल इलाके में सिंधिया की मुश्किलें बढ़ाएंगे ये मंत्री और विधायक

सच संवाददाता ॥ भोपाल

तकरीबन एक महीने पहले बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी को हाईकमान की ओर से भोपाल बुलाकर फटकार लगाई गई थी कि आगे से पार्टी लाइन पर चलेंगे। बीजेपी की छवि प्रभावित करने वाले कोई बयान नहीं देंगे। असर महीना भर भी नहीं रहा। इस बार प्रीतम लोधी का पॉवर और बढ़ा हुआ था। पहले कहा जा चुका है कि हाथ ढाई सौ किलो का हो चुका है और 15 लाख के इनामी डकैत रामबाबू गडरिया को अपना भाई बता दिया। प्रीतम लोधी के इस बयान के ठीक पहले बीजेपी के ही विधायक पन्नालाल शाक्य सिंधिया की सरपस्ती में पार्टी में आकर मंत्री बने विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। मध्य प्रदेश में जिस समय बीजेपी के विधायक अपनी पार्टी के अनुशासन को तार-तार कर रहे हैं। ठीक उसी समय में दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक में प्रदत्ता बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधायक जी ने ये भी कहा कि उनका ढाई सौ किलो का हाथ अब ढाई सौ किलो का हो चुका है। सवाल ये है कि ये ताकत किस

का इलाका कहे जाने वाले ग्वालियर-चंबल और इससे सटे हिस्सों में ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। ये तैवर। कहीं सिंधिया समर्थकों से नाराजगी है, कहीं सिंधिया समर्थक बढ़ रहे हैं टेंशन। एक महीने दस दिन पहले बीजेपी के सिंधिया समर्थक विधायक प्रीतम लोधी भोपाल में थे और और फटकार के बाद मीडिया के कैमरों में खेद जता रहे थे। उम्मीद ये बंधी थी कि ये नसीहत असरदार साबित होगी लेकिन एक बार फिर वायरल हुए प्रीतम लोधी। इस बार उन्होंने दो कदम आगे बढ़कर 15 लाख के -इनामी रहे डकैत को अपना भाई बताया। निशाने पर कौन है ये नहीं पता लेकिन नेताओं से उलट शक्ति प्रदर्शन में विधायक जी ने ये भी कहा कि उनका ढाई सौ किलो का हाथ अब ढाई सौ किलो का हो चुका है। सवाल ये है कि ये ताकत किस



दिया गए प्रीतम लोधी। प्रीतम लोधी के बयानों की फेहरिस्त निकाली जाए तो बीते तीन महीने के भीतर लगातार छोटे बड़े विवाद उनके बयानों से खड़े होते रहे हैं। प्रीतम लोधी से पहले बीजेपी के ही विधायक पन्नालाल शाक्य ने प्रदुम सिंह तोमर बढ़ रही गुटबाजी की पूरी कहानी सड़क पर सुना रहे थे। उनके निशाने पर सिंधिया समर्थक मंत्री थे। विधायक शाक्य ने न केवल इन विधायकों की राजनीति के

अंदाज पर कटाक्ष किया, उनके कामकाज पर भी सवाल उठाया और बयान में एक लकीर खींचते हुए ये बताया कि काम नहीं करने वाले ऐसे विधायकों की वे मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। सवाल ये है कि जो नाराजगी उन्हें पार्टी फोरम पर

मामलों में निशाना सिंधिया पर था। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं बीजेपी की जिस तरह की कार्यप्रणाली है, उसमें एक्शन भी पूरी इत्मीनान से समय देकर लिया जाता है। फिलहाल जिन विधायकों को लग रहा है कि वो सड़क पर बोलकर नोटिस में ले लिए जाएंगे। संगठन के पास इनका भी नोटिस है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर के अनुसार एक अनुशासन ही है जो बीजेपी को कांग्रेस से बिल्कुल अलग करता है। लेकिन ये भी सही है कि लगातार सत्ता में रहने की वजह से अब संगठन निष्ठ भाजपा में भी क्लेश दिखाई और सुनाई देने लगा है। सिंधिया गुट से आए नेताओं को इसमें रचने बसने में लगता है और समय लगेगा। वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता शेहराज खान का कहना है बीजेपी कई गुटों में बंटी है। बीजेपी में बगावती गुटों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिवराज गुट के बाद अजय नाराज गुट, महाराज गुट, तोमर गुट जैसे समूह बन चुके हैं। विधायकों की सुनवाई कही नहीं है। वे बड़े नेताओं को भी अपनी पीड़ा से अवगत करवा चुके हैं। लेकिन सुनवाई कही नहीं है।

संपादकीय विराट और वैभव

भले ही फटाफट क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाला आर्सेणल बाजार और नई पीढ़ी के जुनून का संगम हो, लेकिन लोकप्रियता के नये आयाम तय करता यह खेल अब दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की पहली पसंद बन गया है। इस बार इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे चमकीले सितारे बनकर उभरे टी–20 सनसनी वैभव सूर्यवंशी। महज पंद्रह साल की उम्र में उनकी कामयाबी हैरत में डालने वाली है। वहीं अनुभवी क्रिकेटर विराट कोहली ने अपने खास अंडाज में सबका ध्यान आकर्षित किया। इस 37 वर्षीय दिग्गज क्रिकेटर ने फाइनल में तूफानी अर्धशतक लगाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को लगातार दूसरी बार ट्राफी दिलाई। दो महीने तक चले इस टूर्नामेंट में कोहली की फॉर्म और फिटनेस शानदार रही है। यही वजह है कि उन्हें 2027 एकादिवसीय क्रिकेट के विश्व कप में उनकी भागीदारी अब लगभग तय लग रही है। खुद कोहली ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें अपनी मन:स्थिति में बदलाव लाने और युवा खिलाड़ियों से थोड़ा सीखने की जरूरत थी, ताकि वे टी–20 क्रिकेट में अपने खेल को नये स्तरि से निखार सके। यह सुखद ही है कि इस दिग्गज क्रिकेटर की यह इमानदार स्वीकारोक्ति भारतीय क्रिकेट को आकार दे रही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की खूबसूरत बानगी की ही दर्शाती है। निस्संदेह, हाल ही में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियर लीग सीजन ने साफ दिखाया कि दो पीढ़ियों के क्रिकेटर कैसे एक–दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। वास्तव में, विराट कोहली आज भी एक प्रभावशाली खिलाड़ी की छवि को बनाये हुए हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी जैसे उदीयमान खिलाड़ी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस फटाफट क्रिकेट में खेल का निरंतर विकास होता रहेगा। यह सुखद ही है कि राजस्थान रॉयल्स के इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी सूर्यवंशी ने अधिकांश पुरस्कार अपने नाम किए हैं। मसलन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन, ऑरेंज कैप विजेता और सुपर सिक्स ऑफ द सीजन जैसे खिताब हासिल किए।

इसमें दो राय नहीं कि वैभव सूर्यवंशी के क्रिकेट के वैभव ने आज पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। क्रिकेट की दुनिया के तमाम दिग्गज क्रिकेटर इस उदीयमान खिलाड़ी के क्रिकेट के कारनामों से हतप्रभ हैं। वे वैभव को आशीष व अनुभव दे रहे हैं। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर ने उसे अपना स्वाभाविक क्रिकेट खेलने की सलाह तक दी है। इतना ही नहीं, भारत के चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान में भी वैभव को पूरा लाड मिल रहा है। पूरे पाकिस्तान में उसकी खेल तकनीक की खूब चर्चा होती है। निस्संदेह, उनकी निडर बल्लेबाजी और उल्लेखनीय रूप से निरंतर बेहतर खेलना, क्रिकेट के छोटे प्रारूप के प्रति नई पीढ़ी के साहसिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। हालांकि, उनकी प्रतिभा को लगातार अभ्यास से हासिल व कुछ लोगों द्वारा नैसर्गिक प्रतिभा कहा जा रहा है, लेकिन उन्हें उनकी इतनी कम उम्र में हासिल परिपक्वता को लेकर भी है। सही मायने में दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की सूर्यवंशी की क्षमता ठीक उसी गुण को दर्शाती है,जिसने वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोहली की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है।

भानु सप्तमी से निर्जला एकादशी तक , जून माह के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्ट

साल 2026 का छठा महीना जून कई मायनों में खास रहने वाला है। इस महीने जहां एक ओर भानु सप्तमी, निर्जला एकादशी और शनि त्रयोदशी जैसे महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार पड़ेंगे, वहीं दूसरी ओर कई बड़े ग्रह भी अपनी चाल बदलेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राशि परिवर्तन और नक्षत्र गोचर का सीधा प्रभाव मानव जीवन, मौसम, व्यापार, करियर और पारिवारिक जीवन पर पड़ता है। खास बात यह है कि जून 2026 में चंद्र ग्रह कई बार राशि और नक्षत्र परिवर्तन करेगा, जिससे सभी 12 राशियों पर अलग-अलग असर देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं जून 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहार, शुभ तिथियां और ग्रह गोचर की पूरी लिस्ट।

तिथि	वार	व्रत-त्योहार
3 जून 2026	बुधवार	विभुवन संकष्टी
7 जून 2026	रविवार	अधिक भानु सप्तमी
8 जून 2026	सोमवार	अधिक कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
11 जून 2026	गुरुवार	परम एकादशी
12 जून 2026	शुक्रवार	प्रदोष व्रत (शुक्र) और अधिक कृष्ण रामलक्ष्मण द्वादशी
13 जून 2026	शनिवार	मासिक कार्तिगाई और मासिक शिवरात्रि
14 जून 2026	रविवार	रोहिणी व्रत और अधिक दर्श अमावस्या

ऊर्जा सुरक्षा, भारत की स्थिति व पीएम की यात्राएं

पिछले लगभग 3 माह से चल रहे युद्ध के चलते देश के समक्ष एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है, जो कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, बाधित आपूर्ति आदि के कारण देश में महंगाई बढ़ने लगी है। इसलिए दीर्घकाल के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, वे अल्पकाल के लिए शायद काफी नहीं हैं। देश में आने वाले कुछ समय तक पेट्रोलियम पदार्थों की कमी को भी दूर करना जरूरी है एक ओर अमरीका और इजरायल तथा दूसरी ओर ईरान के बीच युद्ध को लगभग तीन महीने होने जा रहे हैं और यह तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। अमरीका को अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान ने खाड़ी के देशों पर भी हमले किए हैं। लगभग 20 देश युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं। उभर युद्ध रुकवाने के लिए अमरीका पर दबाव बनाने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु एक महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने लगभग बंद कर दिया है। गौरतलब है कि दुनिया के कुल तेल और गैस की 20 फीसदी आवाजाही इस मार्ग से होती है। ऐसे में भारत सहित कई देश तेल और गैस की कमी के कगार पर खड़े हैं। साथ ही साथ युद्ध के चलते तेल और गैस की आवाजाही के बाधित होने से तेल और गैस की कीमतों में भी खासी वृद्धि हुई है और यह लगातार जारी है। भारत में सरकार द्वारा एक्सआईज ड्यूटी घटाकर तेल की कीमतों को स्थिर रखने का बड़ा प्रयास किया गया, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में लगातार होती वृद्धि के कारण अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी वृद्धि प्रारंभ हो गई है। कॉर्पोरेशनल गैस के सिलेंडरों की कीमतों में तो पहले से ही भारी वृद्धि हो चुकी है। हालांकि रसोई गैस की कीमतों को अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन उसमें कमी भी वृद्धि हो सकती है। दूसरी तरफ न्यूकियर देश की कच्चे तेल की लगभग 88 प्रतिशत पूर्ति आयात से होती है, तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण भारत का तेल आयात बिल बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण एक तरफ रुपए में गिरावट हो रही है तो दूसरी तरफ देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली होता जा रहा है। युद्ध के प्रथम तीन महीनों में ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 47 अरब डॉलर कम हो चुका है। इन सब बातों के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि वे पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग को उत्तरोत्तर कम करने का प्रयास करें। इस कारण उन्होंने जनता से वर्क फ्रॉम होम, अधिक सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की भी अपील की है। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडाने के लिए भी उन्होंने सोने की खरीद को कम करने, विदेशी यात्राओं से परहेज करने आदि के लिए भी जनता से गुहार लगाई है। इन परिस्थितियों में मई 2026 के तीसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), होदलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की महत्वपूर्ण यात्राएं आज बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। नौदलिक इन यात्राओं का रणनीतिक संदर्भ भी है। लेकिन माना जा रहा है कि इन यात्राओं के पीछे एक बड़ी प्राथमिकता देश की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग भी है। पश्चिमी एशिया में क्षेत्रीय अस्थिरता और वैश्विक तेल बाजारों में उथल-

चीन की दूरदृष्टि से सबक लेने की जरूरत

यह सब सावधानी से की गई योजनाबंदी से हासिल हो पाया, जिसे पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष स्थान दिया गया (अभी वहां 15वीं योजना चल रही है)। ये योजनाएं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और राज्य परिषद (चीनी कैबिनेट) मिलकर बनाती हैं। यह रणनीतिक बढ़त ही तय करेगी कि देश आगामी ऊर्जा संकट से कैसे निबटेंगा।

ब्लूमबर्ग न्यूज की 28 जनवरी, 2026 की खबर के अनुसार, चीन ने पिछले साल सभी तकनीकी क्षेत्रों में 543 गीगावाट जितनी नई बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भारत में 2024 के आखिर तक के पैदा हुए कुल बिजली उत्पादन से 12 प्रतिशत ज्यादा है। चीन की इस बढ़ोतरी में 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का था, जिसमें सोलर व पवन ऊर्जा शामिल हैं। वहीं यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक तेल भंडार है (लगभग 1.4 अरब बैरल)। दिलचस्प कि उसने 2025 में अपने तेल भंडारण में काफी वृद्धि की, और रूस, ईरान और वेनेजुएला से रियायती दरें पर करोड़ों बैरल तेल खरीदा। जबकि भारत के पास सिर्फ 21 मिलियन बैरल का तेल भंडार था।

पिछले कुछ दशकों में, चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उत्पादन, लिथियम-आयन बैट्री उत्पादन और क्लोन एनर्जी के क्षेत्र में अपनी जुबदस्त रणनीतिक बढ़त बनाई है। चीनी लोग इस समृद्धी मूल्य संवर्धन शृंखला में अब दुनियाभर में अग्रणी हैं। ऐसा कर उन्होंने न केवल जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम की और प्रदूषण घटया बल्कि जीवाश्म ईंधन से दूर हटती दुनिया के दौर में अपनी बहुत मजबूत स्थिति भी बना ली। रेयर अर्थ मिनरल, ईवी निर्माण, बैट्री उत्पादन व स्वच्छ ऊर्जा की यह तिकड़ी, किसी अर्थव्यवस्था को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म करने का 'सबसे अहम माध्यम' है।

यह सब सावधानी से की गई योजनाबंदी से हासिल हो पाया, जिसे पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष स्थान दिया गया (अभी वहां 15वीं योजना चल रही है)। ये योजनाएं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और राज्य परिषद (चीनी कैबिनेट) मिलकर बनाती हैं। यह रणनीतिक बढ़त ही तय करेगी कि देश आगामी ऊर्जा संकट से कैसे निबटेंगा। यह ऊंची और नीची महंगाई दर वाले देशों के बीच का फर्क बनाता है, और यह तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगा कि एआई के युग में डेटा सेंटर कहां स्थापित होंगे, क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, भंडारण, रेयर अर्थ मिनरल और डेटा सेंटरों के बीच एक रणनीतिक सांझ है। बीते साल चीन ने अपने रणनीतिक अस्त्र का इस्तेमाल किया व रेयर अर्थ के निर्यात पर रोक लगाकर भारत का ईवी उत्पादन करीब ठप कर दिया था (इस क्षेत्र में उसका लगभग एकाधिकार है)।

देश –अपनी सरकारों के जरिए– भविष्य के लिए योजना बनाते हैं। ऐसी योजना में विगत के और मौजूदा अनुभवों का गहराई से विश्लेषण करना शामिल होता है, साथ ही भविष्य के संभावित बदलावों के बारे में भी अनुमान भी लगाए जाते हैं। उपरोक्त अवयवों के आधार पर, सरकार भविष्य से निबटने को नीतियां बनाती है। जब हम खुद को और अपनी मौजूदा स्थिति को, खासकर ऊर्जा की स्थिति और उसके नतीजों के मामले में, देखते हैं, तो लगता है कि हमने पिछले कुछ दशक में जरूरी तैयारी नहीं की।

चूँकि भारत का अपना तेल का उत्पादन बहुत कम है, इसलिए यह यकीनी बनाना ईंधन की जम्मेदारी है कि आपात स्थिति में संसाधन उपलब्ध रहें, पर्याप्त



भंडार बनाए, और इससे भी ज्यादा जरूरी यह कि बड़े पैमाने पर हरित ऊर्जा अपनाए, ताकि हम आयातित कच्चे तेल पर बिल्कुल निर्भर न रहें। जहां यह बात तसल्ली देने वाली है कि हमारी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का आधा हिस्सा अब नवीकरणीय स्रोतों से आता है, लेकिन कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन का हिस्सा अभी भी सबसे अधिक (लगभग 42 प्रतिशत) है। अहम बात यह है कि यह अभी भी कुल बिजली खपत का 70 प्रतिशत हिस्सा मुहैया करवाता है, जबकि भारत ने अभी तक बिजली के भंडारण की पर्याप्त क्षमता विकसित नहीं की। जबकि चीन ने इस मामले में बहुत काम किया है। यह दशक लगातार उथल-पुथल भरा रहा। पहले कोविड महामारी, फिर पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया युद्ध जो जारी हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उद्भव। भारत औद्योगिक क्रांति करने से चूक गया था, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। देश '80 और '90 के दशक के कंप्यूटर-प्रधान युग के शुरुआती दौर में भी चूक कर गया; '90 के दशक के आर्थिक सुधार तब जाकर लागू किए, जब देश करीब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। शुक्र है, निजी क्षेत्र ने आगे बढ़कर जम्मेदारी संभाली, साथ ही तकनीकी विशेषज्ञों की बड़ी फौज ने भी स्थिति से उबारने में मदद की। हालांकि भारत अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी नहीं बन पाया, आईटी क्षेत्र में उसकी जगह अधिकांशत: सेवा आधारित क्षेत्र में ही है। हालांकि देर से हुई शुरुआत के मद्देनजर, काबिल-ए-तारीफ है कि हम इतनी प्रगति कर पाए। एआई से आ रहे बड़े बदलावों की बात करें तो, हमने एक बार फिर मौका गंवा डाला है और अब हम उसे तेजी से दूर जाते हुए देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर उत्पादन में हमारी कोई जगह नहीं, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आपूर्ति के लिए एशियाई दिग्गजों– ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन पर निर्भर बना हुआ है। जिन डेटा सेंटरों की स्थापना की योजना बनाई जा रही, वे भी दूसरों पर निर्भर रहेंगे। अमेरिका और चीन ने एआई और उससे जुड़े बुनियादी ढांचा निर्माण में बहुत बड़ी छलांग लगाईं। इस आधारभूत ढांचे में बेहतरीन चिप बनाना, सस्ती बिजली और सरकार का योगदान बतौर सुधारक और मददगार इनका शामिल है। एनवीडिया सरीखी कंपनियां अब खरबों डॉलर मूल्य

की बन चुकी हैं और एआई तकनीक का प्रवाह नियंत्रित करती हैं। किसे ये चिप्स मिल सकती हैं और किसे नहीं, अमेरिका ही तय करता है। एएसएमएल जैसी डच कंपनियां –जो बेहतरीन क्वालिटी के माइक्रोचिप्स उत्पादन के लिए मशीनें बनाती हैं और इस क्षेत्र में उनका करीब एकाधिकार है– सिर्फ उनको ही बेच सकती हैं, जिसको इजाजत अमेरिका देता है। इन सब के बीच हम कहां खड़े हैं? क्या हम एक बार फिर से केवल सेवा और रखरखाव प्रदाता बनने की उम्मीद पाले हैं? जिस स्तर का ऑटोमेशन व रोबोटिक्स सामने आ रहा है, उसे देखकर लगता है,

हमारी यह भूमिका भी बहुत छोटी होकर रह जाएगी। एआई के इस दौर में, अपनी बादशाहत कायम करने की होड़ में जब अलग-अलग देशों के रणनीतिक हित आपस में टकरा रहे हैं, तो ऐसे में एक समझदार और दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत है। एआई आधारभूत तंत्र विकास और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक साझेदारियां बनाने में विदेश नीति और कूटनीति की अहम भूमिका होगी। आज की तारीख में, यहां तक कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रिड स्टोरेज के हेतु बैट्री बनाने की हमारी क्षमता चीन से आयातित 'दुर्लभ खनिजों' पर निर्भर है (इस क्षेत्र में भी चीन का लगभग एकाधिकार)। रणनीतिक गठबंधनों की जरूरत हमें गैस की कमी, और पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध के कारण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के बंद हो जाने से पैदा हुई उर्वरकों और कच्चे तेल की संभावित कमी व आपूर्ति शृंखला में रुकावटों के रूप में साफ दिखती है। हमें मजबूरन हाथ-पैर मारने पड़ रहे, दूसरों से मदद मांगनी पड़ी। रूस संग हमारा भी समझौता था, चीन की तरह, लेकिन रूस पर प्रतिबंधों का सर्वाधिक नुकसान हमें उड़ाना पड़ा।

इसी तरह, अब हमें ईरान से भी तेल नहीं मिल पा रहा है। हमारी भंडारण क्षमता भी सीमित है, और हमसे हाल ही में यूएई के साथ मिलकर बड़े-बड़े तेल भंडार बनाने का समझौता किया है... लेकिन इसको फलीभूत होने में अभी काफी समय लगेगा। अमेरिका-ईरान युद्धबंदी वार्ता नाकाम होना हमारे लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा और इससे अफ़रा-तफ़री मच सकती है – ऐसी स्थिति से हम अब तक किसी तरह बचे हुए थे। इसके साथ ही, अमेरिका पाकिस्तान और उसके फोल्ड मार्शल की पीट ठोक रहा है, और ईरान के मामले में उस पर एक महत्वपूर्ण मिश्रस्थ के रूप में भरोसा करता है। आर्थिक दुश्चारियों से राहत पाने में अमेरिका ने विश्व बैंक के जरिए उसकी मदद की है।

इस चोतरफा हमले का सामना करने के लिए पूरे देश का एकजुट रहना जरूरी है। इस पहल को शुरुआत भारत सरकार के नेतृत्व से होनी चाहिए।

–**गुवचन सिंह जगत लेखक मणिपुर के राज्यपाल एवं जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक रहे हैं।**

मुस्लिम ने मुस्लिम को खदेड़ा

घुसपैठियों का मुद्दा सामान्य नहीं, बेहद संवेदनशील और पेचोदा है। कूटनीति और बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों पर तनाव बढ़ सकता है। यह भारत की ही समस्या नहीं, बल्कि खाड़ी के मुस्लिम देश, यूरोप, ब्रिटेन और अमरीका भी परेशान हैं। अंततः घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है। ऐसे सभी लोग घुसपैठिए भी नहीं हैं। बहरहाल सिर्फ मुस्लिम देशों के ही कुछ उदाहरण लें, तो साफ होगा कि यह कितना नाजुक और बिलबिला देने वाली समस्या है। पाकिस्तान ने बीते सालों में 1.46 लाख से अधिक अफगानी मुसलमानों को उनके देश वापस जाने को विवश किया है। दोनों इस्लामी देश हैं। ईरान आज युद्ध में घिरा है, लेकिन इससे पहले वह करीब 15 लाख मुसलमानों को देश से खदेड़ चुका है। संयुक्त अरब अमीरात के स्वर्निल, शानदार शहर दुबई जाने को आधुनिक युवा हरचंद कोशिश करते हैं। वहाँ नौकरियों के मुठे पैकेज मिलते हैं और व्यापार की चौरफा संभावनाएं हैं। दुबई 'धन्नासेठों का शहर' भी है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात ने ही 7500 से अधिक पाकिस्तानी लोगों को वापस जाने को विवश किया है। उन्हें अपना सामान पैक करने तक का वक्त नहीं दिया गया। तुर्किए खुद को मुसलमानों का 'खलीफा देश' मानता है। उसने भी करीब 2.60 लाख लोगों को देश छोड़ कर चले जाने को बाध्य किया है। जॉर्डन ने जिन 6.75 लाख के करीब लोगों को, खेती का काम करने को, शरण दी थी, उनमें से 1.5 लाख से अधिक शरणार्थियों को वह खदेड़ चुका है।सऊदी अरब ने तो हद ही कर दी, जब 18,836 कथित अवैध, अर्वाञ्छित अप्रवासियों को हथकड़ी लगाकर देश के बाहर किया गया। अमरीका ने भी हथकड़ी, बेडियां बांध कर भारतीयों को वापस भेजा था और हम एक राष्ट्र के तौर पर 'चू' तक नहीं कर पाए थे। इसी तरह मुस्लिम देश अधिकतर मुसलमानों को ही निष्कासित कर रहे हैं, तो किसी भी देश ने इसे उनका एजेंडा करार नहीं दिया। मानवाधिकार के नाम पर या तो मुंह में दही जम गया अथवा आंखें मूंद ली गईं। दुनिया ने इस 'खदेड़बाजी' को राष्ट्रीय सुरक्षा और उन देशों के संसाधनों का राष्ट्रीय प्रबंधन मान लिया, लेकिन भारत में, खासकर बंगाल से, घुसपैठियों को देश से बाहर करने के मुद्दे पर एक राजनीतिक, सामाजिक, मजहबी तबका बिलबिलाने क्यों लगता है ? राज्यसभा में भारत सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि देश में करीब 2 करोड़ घुसपैठिए हैं। विशेषज्ञ यह संख्या 3-4 करोड़ आंकते हैं। क्योंकि बंगाल के अलावा, उप्र, बिहार, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि राज्यों से लेकर राजधानी दिल्ली में भी घुसपैठिए हैं।



पुथल के चलते यह स्पष्ट है कि भारत इस यात्रा को परंपरागत तेल की आपूर्ति और भविष्य के लिए हरित ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनाओं को बढ़ाने में सफल हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात भारत के तेल आयात का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है, जहां से भारत की कुल कच्चे तेल की आपूर्ति का 11 प्रतिशत प्राप्त होता है। तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में यूएई का तीसरा स्थान है और भारत यूएई की गैस का सबसे बड़ा खरीददार है। एलपीजी के लिए भी यूएई भारत का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरी तरफ भारत द्वारा परिष्कृत पेट्रोलियम और लुब्रीकेंट का निर्यात भी यूएई में बड़ी मात्रा में होता है और इस संदर्भ में भी उसका दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। भारतीय कंपनियों ने बड़ी मात्रा में यूएई की ऊर्जा परिसंपत्तियों में निवेश किया हुआ है। यूएई की कंपनी 'मसदर' ने राजस्थान में 60 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माण के लिए समझौता किया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की यात्राओं में यूएई की यात्रा प्रारंभ में शामिल नहीं थी, और अंतिम समय पर 15 मई के लिए यूएई की यात्रा को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जोड़ा गया। यात्रा क्रम में इस बदलाव को कूटनीतिक और आर्थिक हलकों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे खास यह रही कि आपातकाल में भारत के पेट्रोलियम भंडार की आवश्यकता पूर्ण करेगा और ऐसी किसी भी स्थिति में भारत को गारंटी के साथ तेल की आपूर्ति की जा सकेगी। हालांकि भारत के पास तेल के भंडारण की काफी क्षमता है, लेकिन उसके बावजूद भी युद्धकाल में ऐसा देखा गया कि यह क्षमता युद्ध के स्थिति में अपयुक्त है। अबूधाबी नेशनल आयल कंपनी और इंडियन आयल लिमिटेड के बीच एक सहयोग समझौता हुआ, जिससे भारत की एलपीजी आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यूएई की यात्रा में खास बात रणनीतिक प्रतिरक्षा साझेदारी का फ़ेमवर्क भी शामिल है। इसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच प्रतिरक्षा और प्रौद्योगिक सहयोग को मजबूत किया जाएगा। जलपोत मरम्मत हेतु

विधायक ट्रॉफी-2026 का रंगारंग आगाज

खेलों से शारीरिक और नेतृत्व का क्षमता का होता है विकास : सबनानी

सच संवाददाता ॥ भोपाल।

विधानसभा क्षेत्र में विधायक ट्रॉफी 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के अवसर पर करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य महाराज विधायक भगवानदास सबनानी जिला अध्यक्ष रविंद्र यती रहे मौजूद। इस अवसर पर विधायक भगवानदास सबनानी ने उपस्थित सभी खिलाड़ियों और दर्शकों का स्वागत किया उन्होंने कहा कि खेल जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है खिलाड़ियों का अनुशासन उनका परिचय देता है, अनुशासित खिलाड़ी ही सफलता प्राप्त करता है, खेलों से जीवन में अनुशासन मानसिक विकास चरित्र निर्माण और नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होता है। हमारी दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमारा क्षेत्र शहर का हृदय स्थल है यहां पर हर वर्ग की प्रतिभाएं निवास करती हैं।



मेरा प्रयास रहता है कि हमारे क्षेत्र की प्रत्येक प्रतिभाओं को सम्मान मिले और वह अपनी प्रतिभा से प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, साथ ही कहना चाहूंगा कि मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, खेल और खिलाड़ियों की भावना से भली-भांति परिचित हूँ, खेल का उद्देश्य केवल हार और जीत का परिणाम नहीं, बल्कि मैदान पर संघर्ष, अनुशासन, टीम भावना और मानवीय मूल्यों को सीखना है।

1 जून से 9 जून तक टैनिंस बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन नेहरू नगर पुलिस ग्राउंड

में नवप्रयास सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट में 32 टीमों में भाग ले रही हैं, नॉकआउट मैचों के साथ 9 जून को फाइनल खेला जाएगा। शुभारंभ के साथ डॉक्टर वर्सेस पत्रकारों का एक शो मैच हुआ, जिसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक था। प्रतिदिन x से 4 मैच 8 ओवरों के खेले जाएंगे। शुभारंभ पर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में दर्शन उपस्थित रहे और उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया।

मैच अरेरा ग्रीन और ब्लू के बीच हुआ फाइनल मुकाबला

अरेरा प्रीमियर इंटर हाउस क्रिकेट लीग प्रतियोगिता

सच संवाददाता ॥ भोपाल।

अरेरा प्रीमियर इंटर हाउस क्रिकेट लीग प्रतियोगिता में अन्तिम दिन सीनियर एज ग्रुप में फाइनल मैच अरेरा ग्रीन और ब्लू के बीच हुआ। ग्रीन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.2 ओवरों में सभी विकेट खोकर 251 रन बनाए। रुद्र तेनगुरिया ने 94, नीर जोवर ने 55.0 तेजस लोधी और आशुतोष गिरि ने 27-2 7 रन बनाए। गेंदबाजी में नीरज गोरव, रोशन नायक, अर्जुन शुक्ला और लकी सूर्यवंशी ने 2-2 विकेट लिए। 2 बल्लेबाज रन आउट हुए। जवाब ब्लू हाउस 32.3 ओवरों में सभी विकेट खोकर 141 रन बनाए। अर्जुन शुक्ला ने 60, नीरज गोरव ने 38 और पीयूष सिंह ने 19 रन बनाए। ग्रीन हाउस की ओर से हर्षित ओझा ने 4 और प्रतीक शुक्ला ने 3 विकेट लिए। ग्रीन हाउस 110 रनों से विजय प्राप्त कर

चैम्पियन बना। रुद्र तेनगुरिया प्लेयर ऑफ द मैच बने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अर्जुन शुक्ला बेस्ट बैट्समैन नीरज गोरव, बॉलर द्रोण श्रीवास्तव, विकेटकीपर तेजस लोधी फील्डर आशुतोष गिरि बने प्रतियोगिता के अंत में माननीय श्री विश्वास सारंग जी, खेल एवं सहकारिता, मध्य प्रदेश के मुख्य आतिथ्य में एवं विशिष्ट अतिथि श्री शान्ति जैन सचिव बीडीसीए, अजय श्रीवास्तव, नीलू महासचिव, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, प्रदेश अध्यक्ष निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी महासंघ, द्वारा पुरस्कार वितरण सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर श्री अविनाश बुरबुरे, समीर मिरिकर, पारितोष शर्मा, मानसिंह, मुकेश भटनागर, महेश प्रजापति एवं प्रियदर्शिनी पाठक एवं अनेक पालकगण एवं प्लेयर्स उपस्थित हुए।

सिंधु सेना भोपाल द्वारा आयोजित नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन

आरबीएम पिढी 11 बनी सिंधी सुपर किंग्स-2026 की चैंपियन

सच संवाददाता ॥ भोपाल।



सिंधु सेना भोपाल द्वारा लगातार 9वें वर्ष आयोजित सिंधी प्रीमियर लीग-सीजन 9 का भव्य समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में आरबीएम पिढी 11 ने संत हिरदाराम 11 को हराकर 'सिंधी सुपर किंग्स-2026' का खिताब अपने नाम किया।

फाइनल मुकाबले में संत हिरदाराम 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 94 रन बनाए। जवाब में आरबीएम 11 ने यह मैच 5 विकेट से जीत लिया। पलाश को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार आरबीएम 11 के पलाश को मिला, जिन्होंने 220 रन बनाए। बेस्ट बॉलर का खिताब यूसीसी के राहुल मनचंदा को मिला, जिन्होंने 10 विकेट लिए। बेस्ट फील्डर संत हिरदाराम 11 के

पीयूष चुने गए एवं मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार घराना 11 के मोहित सचदेवा को दिया गया, जिन्होंने 210 रन और 5 विकेट लिए। टूर्नामेंट में भोपाल की 16 टीमों ने भाग लिया। विजेता टीम आरबीएम पिढी 11 को 1 लाख 51 हजार रुपये नकद एवं विजेता ट्रॉफी प्रदान की गई, जबकि उपविजेता संत हिरदाराम 11 को 51 हजार रुपये नकद एवं ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। समापन समारोह में जिलाध्यक्ष रविंद्र यती मुख्य अतिथि के रूप में

उपस्थित रहे। उन्होंने विजेता एवं उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजक राकेश कुकरेजा ने कहा, सिंधी समाज केवल व्यापार में ही नहीं, खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। सिंधी समाज के युवा फिट रहें, स्वस्थ रहें, इसी उद्देश्य से सिंधु सेना पिछले 9 वर्षों से लगातार नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है। समाज के युवाओं को पूरे साल एस्पिरेशन का इंतजार रहता है। टूर्नामेंट के सफल आयोजन में सिंधु सेना के दर्शन कुकरेजा, अनिल थारवानी, विकास वाधवानी, यशपाल तनवानी, राहुल तलरजा, सुनील कुकरेजा, नरेश गोलेनी एवं सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा।

सच बाजार

गोल्ड लोन लेने वालों का तांता

बैंकों में उमड़ी भीड़: महंगे गोल्ड से लोग उठा रहे डबल फायदा

वाणिज्य संवाददाता.भोपाल

सोने की रिकॉर्ड उंची कीमतों ने जहां आम खरीदारों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर यह महंगा सोना लाखों लोगों के लिए आसान फंडिंग का जरिया बन गया है। भोपाल, मध्यप्रदेश में बैंकों और वित्तीय संस्थानों में गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात ऐसे हैं कि वित्त वर्ष 2026 में गोल्ड लोन सबसे तेजी से बढ़ने वाले सिक्योरिटी लोन सेक्टर के रूप में उभरकर सामने आया है।

जानकारी के अनुसार सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण लोगों को अपने पुराने गहनों और गोल्ड एसेट्स पर पहले से ज्यादा लोन मिल रहा है। यानी सोना बेचने की जरूरत नहीं पड़ रही और उसकी कीमत बढ़ने का लाभ भी बना हुआ है। दूसरी तरफ उसी सोने को गिरवी रखकर तत्काल नकदी हासिल की जा रही है। यही वजह है कि निवेशक और आम उपभोक्ता दोनों गोल्ड लोन को बेहतर विकल्प मान रहे हैं। बाजार जानकारों के अनुसार गोल्ड लोन का औसत टिकट साइज भी तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024 में जहां औसतन एक लाख रुपए का गोल्ड लोन लिया जा रहा था, वहीं वित्त वर्ष 2026 में यह बढ़कर 1.7 लाख रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि होम लोन अब भी सबसे बड़ी लोन कैटेगरी बना हुआ



है, जिसका औसत आकार करीब 33.5 लाख रुपए है, लेकिन वृद्धि दर के मामले में गोल्ड लोन ने सभी को पीछे छोड़ दिया है।

कम कागजी कार्रवाई और सुरंत पैसा बना आकर्षण

सर्राफा महासंघ भोपाल के संगठन महामंत्री, प्रवक्ता नवनीत अग्रवाल ने बताया कि गोल्ड लोन की लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ा कारण इसकी आसान प्रक्रिया है। अन्य लोन की तुलना में इसमें दस्तावेज कम लगते हैं, क्रेडिट स्कोर की बाध्था सीमित होती है और कुछ ही घंटों में राशि मिल

जाती है। यही वजह है कि छोटे कारोबारियों, किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों के बीच इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। उनके अनुसार गोल्ड लोन की मांग बढ़ने के पीछे एक और बड़ा कारण भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से अनसिक्योरिटी लोन पर बढ़ाई गई निगरानी और सख्ती को माना जा रहा है। पर्सनल लोन और अन्य बिना गारंटी वाले कर्जों पर सख्त नियम लागू होने के बाद लोग अब सिक्योरिटी लोन की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में गोल्ड लोन सबसे आसान और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। वित्तीय विशेषज्ञों में शामिल करसलाहाकार राजेश जैन का कहना है कि यदि सोने की कीमतों में मजबूती बनी रहती है तो आने वाले महीनों में गोल्ड लोन बाजार और तेजी से विस्तार कर सकता है। हालांकि उधारकर्ताओं को यह भी ध्यान रखना होगा कि समय पर भुगतान नहीं करने पर गिरवी रखा गया सोना नीलाम किया जा सकता है।

सर्राफा कारोबारियों आनंद सोनी के अनुसार सोने की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने गोल्ड लोन की मांग को सीधे तौर पर बढ़ावा दिया है। व्यापारियों के अनुसार, पहले लोग जरूरत पड़ने पर सोना बेचने का विकल्प चुनते थे, लेकिन अब बढ़ती कीमतों के कारण ग्राहक अपने गहने

बेचना नहीं चाहते। इसके बजाय वे गोल्ड लोन लेकर तत्काल नकदी की जरूरत पूरी कर रहे हैं और भविष्य में सोने की कीमत बढ़ने का लाभ भी बनाए रखना चाहते हैं। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि बाजार में ग्राहकों की सोच बदली है। लोग अब सोने को केवल आभूषण नहीं, बल्कि एक मजबूत वित्तीय संपत्ति के रूप में देखने लगे हैं। यही कारण है कि गोल्ड लोन कंपनियों और बैंकों में ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

बैंकिंग सेक्टर की राय

बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा समय में गोल्ड लोन सबसे सुरक्षित और तेजी से बढ़ने वाले रिटेल लोन उत्पादों में शामिल हो गया है। बैंकों के अनुसार सोने की बढ़ती कीमतों ने ग्राहकों की उधार लेने की क्षमता बढ़ा दी है, जिससे उन्हें पहले की तुलना में अधिक राशि का लोन मिल रहा है। बैंक अधिकारियों का मानना है कि अनसिक्योरिटी लोन की तुलना में गोल्ड लोन में जोखिम कम होता है क्योंकि इसके बदले बैंक के पास सोने के रूप में पर्याप्त सुरक्षा होती है। यही वजह है कि कई बैंक और वित्तीय संस्थान इस सेगमेंट पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और ग्राहकों के लिए आकर्षक योजनाएं पेश कर रहे हैं।

श्रीजी शिपिंग को आयकर विभाग की मंजूरी

मुंबई। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड को आयकर विभाग से टनेज टैक्स स्कीम) के तहत मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय 12-जी की धारा 115वीपी (1) के अंतर्गत कंपनी के पात्र अंतर्देशीय जहाजों के लिए प्रदान की गई है। कंपनी के अनुसार यह मंजूरी वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) से प्रभावी होगी और वित्त वर्ष 2034-35 तक अथवा लागू नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि तक वैध रहेगी। यह लाभ आयकर अधिनियम और संबंधित नियमों के अनुपालन को शर्तों के अधीन लागू रहेगा। कंपनी ने इस मंजूरी को अपनी विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। कंपनी का मानना है कि टनेज टैक्स स्कीम से दीर्घकालिक कर नियोजन में स्पष्टता मिलेगी और पात्र शिपिंग परिचालनों में कर दक्षता बहेगी। टनेज टैक्स स्कीम के तहत शिपिंग कंपनियों पर कर का निर्धारण उनके वास्तविक लाभ के बजाय जहाजों की शुद्ध वजन क्षमता के आधार पर किया जाता है। इससे कर देनदारी अधिक स्थिर और पूर्वानुमेय रहती है, जिससे कंपनियों को बेहतर वित्तीय योजना बनाने में मदद मिलती है।

जेनएक्सएआई एनालिटिक्स का आईपीओ 5 को खुलेगा

मुंबई। जेनएक्सएआई एनालिटिक्स लिमिटेड ने अपने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम को शुक्रवार, 5 जून 2026 को खोलने का प्रस्ताव रखा है। कंपनी का लक्ष्य ऊपरी प्राइस बैंड पर 54.66 करोड़ रुपए जुटाने का है। इस इश्यू का आकार 47,28,00 इंडिक्टी शेयरों का है, जिनका अंकित मूल्य 18 रुपए प्रति शेयर है। आईपीओ का प्राइस बैंड 110 से 116 रुपए प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। आईपीओ से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग नए उत्पादों के विकास के लिए, पूंजीगत व्यय, उधारों के पुनर्भुगतान, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं तथा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली प्रक्रिया गुरुवार, 04 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। यह इश्यू शुक्रवार 5 जून 2026 को खुलेगा और मंगलवार 9 जून 2026 को बंद होगा।

125 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर से सथलोखर सिनर्जीज की ऑर्डर बुक 840 करोड़ के पार

चेन्नई। सथलोखर सिनर्जीज ई एंड सी ग्लोबल लिमिटेड को लगभग 125 करोड़ रुपए के नए पुष्ट ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। इन नए प्रोजेक्ट्स के साथ कंपनी की वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल पुष्ट ऑर्डर बुक बढ़कर 840.22 करोड़ रुपए हो गई है, जिससे आने वाले समय के लिए मजबूत राजस्व संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कंपनी को मिले नए ऑर्डर औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों से संबंधित हैं, जो उसकी मजबूत निष्पादन क्षमता और ग्राहकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाते हैं।

सथलोखर सिनर्जीज को ग्रैंड अटलांटिया पनपकम एसईजेड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से चेन्नई के रानीपेट स्थित शिपकोट पार्क में सिविल और प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग निर्माण कार्य का बड़ा ऑर्डर मिला है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 105.37 करोड़ रुपए है। परियोजना के तहत वर्कशॉप भवनों, सहायक संरचनाओं और पार्किंग सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसे मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी को इसी औद्योगिक परियोजना के फेज-1बी के लिए 22.53 करोड़ रुपए का एक और सिविल एवं पीईसी निर्माण कार्य का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इस कार्य के फरवरी 2027 तक पूर्ण होने की उम्मीद है। कंपनी ने महाराष्ट्र में भी अपनी उपस्थिति मजबूत करते हुए सीलोन बेवरेज कैन प्राइवेट लिमिटेड से 15.36 करोड़ (जीएसटी सहित) का ऑर्डर हासिल किया है।

होंडा की बिक्री 12 फीसदी बढ़ी, 5.18 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज

गुरुग्राम। होंडा मोटर्सइंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मई 2026 में कुल 5,18,777 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है। यह आंकड़ा मई 2025 में बेची गई 4,65,109 यूनिट्स की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है, जो कंपनी की मजबूत बाजार उपस्थिति और उपभोक्ता मांग को दर्शाता है। कंपनी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में फोर्ल्स बाजार में 4,59,611 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो पिछले वर्ष के इसी महीने की 4,17,250 यूनिट्स की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि है। वहीं, निर्यात के क्षेत्र में भी कंपनी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। मई 2026 में 59,166 यूनिट्स का निर्यात किया गया, जो मई 2025 के 47,859 यूनिट्स के मुकाबले 24 प्रतिशत अधिक रहा। एचएएमएसआई ने अपने विविध उत्पाद पोर्टफोलियो और देशभर में फैले 7,000 से अधिक टचपॉइंट्स के व्यापक नेटवर्क के जरिए ग्राहकों तक पहुंच को और मजबूत किया है।

डाबर रियल एक्टिव कोकोनट वॉटर पेश

नई दिल्ली। आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड ने अपने प्राकृतिक हाइड्रेशन समाधान रियल एक्टिव कोकोनट वॉटर को पेश किया है। यह नारियल पानी शरीर को नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान करता है और बिना किसी अतिरिक्त चीनी के तैयार किया गया है, जिससे यह एक स्वास्थ्यवर्धक और लो-कैलोरी विकल्प बन जाता है। डाबर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट-मार्केटिंग मयंक कुमार ने बताया कि रियल एक्टिव कोकोनट वॉटर गर्मियों का एक परफेक्ट साथी है। यह शरीर को हाइड्रेट रखता है, थकान को दूर करता है और पानी की कमी को पूरा करता है। इसमें किसी प्रकार की अतिरिक्त चीनी नहीं मिलाई गई है, इसलिए इसे बिना किसी फिफ्ट के लिया जा सकता है। इसके फेट-फ्री और लो-कैलोरी होने के कारण यह बाजार में मौजूद ज्यादा चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा के मुकाबले एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरता है।

जॉनसंस बेबी ने लांच की नई मिल्क एंड राइस रेंज

मुंबई। जॉनसंस बेबी ने अपनी नई मिल्क एंड राइस रेंज लांच की है। लांच की थीम पोषण का पहला स्पर्श अपनी तरह की पहली सांस्कृतिक अवधारणा के माध्यम से, बच्चों की त्वचा को सही आहार देने का दुनिया का पहला अनोखा तरीका है। इस खास मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्री और इस रेंज की ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा भी शामिल हुईं, जिन्होंने 30 माताओं और उनके बच्चों के साथ मिलकर इस नए स्किनकेयर रिचुअल की शुरुआत का जश्न मनाया।

रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च की नई बुलेट 650



नई दिल्ली। मिडसाइज मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड ने भारत में अपनी आइकॉनिक बुलेट का नया 650सीसीवर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे गोल्ड स्कूल फॉरएवर थीम के साथ पेश किया है, जो क्लासिक डिजाइन और आधुनिक तकनीक का मेल है। नई बुलेट 650 को दो आकर्षक रंगों कैनन ब्लैक और बैटलशिप ब्लू में लांच किया गया है।

बैंक खाते से सीधे जमा और निकासी संभव कॉइनबेस ने भारत में शुरू की डायरेक्ट रुपए ट्रांजेक्शन सुविधा

एजेंसी.मुंबई वैश्विक क्रिप्टोकॉर्सेस एक्सचेंज और एसएंडपी-500 इंडेक्स में शामिल कंपनी कॉइनबेस ने भारतीय ग्राहकों के लिए डायरेक्ट रुपए में लेनदेन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस नई सुविधा के तहत भारतीय उपयोगकर्ता अब आईएमपीएस के माध्यम से सीधे अपने बैंक खातों से रुपए जमा और निकासी कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें किसी पी2पी नेटवर्क या अन्य विनोदियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

कंपनी ने बताया कि वह भारत की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स यूनियन के साथ पंजीकृत है और भारतीय नियामकीय ढांचे का पूर्ण रूप से पालन करती है। नए सिस्टम के जरिए ग्राहकों को अधिक सहज, तेज और सुरक्षित लेनदेन का अनुभव मिलेगा। कॉइनबेस ने भारतीय ग्राहकों के लिए स्थानीय

एनबीबीएल के भारत कनेक्ट पर ई-चालान ने 10 लाख ट्रांजेक्शन पार किए

भोपाल। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की सहायक कंपनी, एनपीसीआई भारत बिलपेयि लिमिटेड (एनबीबीएल) ने भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर अपनी ई-चालान सेवा में 10 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन पूरे होने की घोषणा की। इन ट्रांजेक्शन का कुल मूल्य 60 करोड़ रुपये से अधिक है। इस सुविधा के जरिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के नागरिक अब अपने ट्रेफिक चालान देख और उनका भुगतान सुरक्षित, आसान और इंटरऑपरैबल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में इस सेवा का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है, जहां 7 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन हुए हैं, इसके बाद तेलंगाना और गुजरात का स्थान है। दिल्ली और हिमाचल



प्रदेश हाल ही में प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। एनबीबीएल की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी, डॉ. नूपुर चतुर्वेदी ने कहा कि यह उपलब्धि लोगों के प्लेटफॉर्म पर भरोसे को दर्शाती है और दिखाती है कि नागरिक डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हम अपने भागीदारों के साथ मिलकर इसे और अधिक राश्यों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ई-चालान की सफलता डिजिटल संचालन को दिशा दे रहा है और महत्वपूर्ण कदम है और यह राज्य-स्तरीय ट्रेफिक नियमों को भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जोड़ता है।

सामाजिक उत्थान में अग्रणी महर्षि संस्थान, शिक्षा और वैदिक ज्ञान के प्रसार में निभा रहा महत्वपूर्ण भूमिका

सच संवाददाता.भोपाल

भारत के महान संत एवं आध्यात्मिक गुरु महर्षि महेश योगी के विचारों और दर्शन को आगे बढ़ाते हुए महर्षि संस्थान देशभर में शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदिक ज्ञान और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। महर्षि महेश योगी का जन्म 12 जनवरी 1917 को पांडुका में हुआ था। उन्होंने प्राचीन वैदिक ज्ञान को वैज्ञानिक आधार देकर विश्वभर में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रचार-प्रसार किया।

महर्षि ने वर्ष 1957 में ट्रान्सेडेंटल मेडिटेशन पद्धति को विश्व समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किया। यह एक सरल, स्वाभाविक और प्रयासहीन ध्यान तकनीक है, जिसके नियमित



अध्यास से मानसिक शांति, रचनात्मकता और समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है। उनके

द्वारा प्रतिपादित 'महर्षि प्रभाव' सिद्धांत के अनुसार सामूहिक ध्यान से समाज में सकारात्मकता और शांति का वातावरण निर्मित होता है।

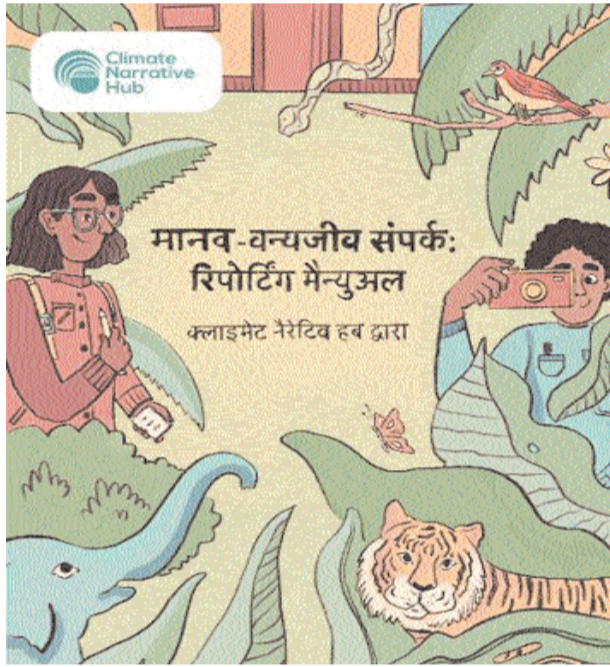
महर्षि संस्थान द्वारा देशभर में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान में 153 महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय संचालित हैं, जिनमें एक लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और भावनात्मक ध्यान का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। भोपाल स्थित महर्षि सेंटर फॉर एजुकेशनल एक्सप्लोरेशन में केजी से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा एक ही परिसर में उपलब्ध है। वहीं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय और महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ

मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हजारों विद्यार्थियों को वैदिक ज्ञान और आधुनिक उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है।

प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में भोपाल और इंदौर स्थित महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं देश के 14 स्थानों पर संचालित महर्षि वेद-विज्ञान विश्व विद्यापीठों में लगभग 9,000 विद्यार्थियों को वेद एवं कर्मकांड की शिक्षा निःशुल्क आवास और छात्रवृत्ति के साथ प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भोपाल स्थित महर्षि वैदिक हेल्थ सेंटर आयुर्वेद, पंचकर्म, योग, ज्योतिष और वैदिक उपचार पद्धतियों के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा भावनात्मक ध्यान और ध्यान-सिद्धि कार्यक्रमों के लिए विश्वभर में

हजारों प्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत हैं तथा एक करोड़ से अधिक लोग इन कार्यक्रमों का अभ्यास कर रहे हैं। महर्षि संस्थान द्वारा पिछले 15 वर्षों से 'महामीडिया' पत्रिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है, जिसमें महर्षि के दर्शन, वैदिक ज्ञान और समसामयिक विषयों पर लेख प्रकाशित किए जाते हैं। वर्ष 2008 में महर्षि महेश योगी के ब्रह्मलीन होने के बाद भी उनके विचारों और ज्ञान परंपरा का विस्तार निरंतर जारी है। संस्थान भविष्य में महर्षि किड्स होम, महर्षि ज्ञान स्तंभ, नए महर्षि विद्या मंदिर विद्यालयों और सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना जैसी योजनाओं पर कार्य कर रहा है, ताकि शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में समाज को और अधिक लाभ मिल सके।

मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व की कहानियों पर नई गाइड जारी



विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और द नेचर कंजर्वेन्सी-इंडिया जैसे कई संगठनों ने सहयोग किया। इसमें रिपोर्ट्स को यह समझने के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि जानवर किसी क्षेत्र में क्यों आते हैं, उनके आवास, जलवायु परिवर्तन या भोजन की उपलब्धता जैसे कारणों पर ध्यान देना जरूरी है। गाइड सह-अस्तित्व के पहलुओं पर भी जोर देती है कैसे समुदाय अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं, जोखिम को कम करने के उपाय अपनाते हैं और वन्यजीवों के साथ सुरक्षित सह-जीवन सुनिश्चित करते हैं। यह पत्रकारों और कहानीकारों को स्थानीय, आदिवासी और जंगल समुदायों की आवाज सुनने और उनके अनुभवों को शामिल करने के लिए प्रेरित करती है।

सच संवाददाता ॥ भोपाल।

क्लाइमेट नैरेटिव हब (सीएनएच) ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नई गाइड जारी की है, जो मानव-वन्यजीव संघर्ष से परे सह-अस्तित्व की कहानियों को सामने लाने के लिए प्रेरित करती है। यह गाइड उन रिपोर्टर्स के लिए है जो वन्यजीवों और इंसानों के बीच होने वाले संघर्ष को कवर करते हैं, लेकिन अक्सर सिर्फ हमलों या मौतों जैसी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर बैठते हैं।

गाइड तैयार करने में नेटवर्क फॉर कंजर्विंग सेंट्रल इंडिया, वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी-इंडिया, को-एक्सिस्टेंस कंसोर्टियम, द कॉर्बेट फाउंडेशन,

आरएनटीयू में होराइजन 2026 के तहत विद्यार्थियों को दी गई भावभीनी विदाई



सच संवाददाता ॥ भोपाल।

रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में हाल ही में होराइजन 2026 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भावभीनी विदाई समारोहों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स तथा पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सत्र 2026 बैच के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, प्राध्यापकों एवं जूनियर्स ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए यादगार पलों को साझा किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और भावनात्मक पलों ने बनाया समारोह को यादगार

समारोह में जूनियर विद्यार्थियों ने अपने सीनियर्स के सम्मान में रंगारंग सांस्कृतिक

प्रस्तुतियां दीं। समूह नृत्य, गीत, मिमिक्री, मनोरंजक एक्ट्स और भावनात्मक प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को उल्लास और संवेदनाओं से भर दिया। कार्यक्रम की सबसे विशेष प्रस्तुति तब देखने को मिली जब विद्यार्थियों ने अपने प्रिय मेंटर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. योगेश पटेल को समर्पित कविता पाठ और गीत प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों द्वारा डॉ. योगेश पटेल को हाथ से तैयार किया गया एक विशेष पेंसिल स्केच भेंट किया गया, जिसने समारोह को और अधिक भावुक बना दिया। वहीं बीते तीन वर्षों की कक्षाओं, मॉडिया प्रैक्टिकल्स, स्टूडियो गतिविधियों और विश्वविद्यालयीन आयोजनों पर आधारित विशेष वीडियो प्रस्तुति ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को पुरानी यादों को ताजा कर दिया।

विश्वविद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की प्रयोगशाला : डॉ. रुचि

फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स की डीन डॉ. रुचि मिश्रा तिवारी ने

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्राप्त करने का स्थान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की एक सशक्त प्रयोगशाला है। यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी अपने ज्ञान, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक सोच के माध्यम से समाज में नई दिशा देने का कार्य करें।

रचनात्मकता और अनुशासन के लिए याद रखा जाएगा यह बैच : डॉ. अंजली

विभागाध्यक्ष डॉ. अंजली तिवारी ने कहा, सत्र 2026 का यह बैच अपनी रचनात्मकता, अनुशासन, टीम भावना और हर गतिविधि में सक्रिय सहभागिता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। विभाग को अपने विद्यार्थियों पर गर्व है।

विद्यार्थियों का स्नेह ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि : डॉ. योगेश पटेल

विद्यार्थियों के मेंटर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. योगेश पटेल ने कहा, इन विद्यार्थियों के साथ बिताया गया यह सफर केवल शिक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव में परिवर्तित हो गया।



आरकेडीएफ विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, सिकल सेल एनीमिया जागरूकता पर जोर

सच संवाददाता ॥ भोपाल।

आरकेडीएफ विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित विशेष कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं द्वारा सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का आयोजन मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल के जन्मदिवस के अवसर पर किया गया।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉ. साधना कपूर, कुलगुरु प्रो. विजय अग्रवाल, प्रबंध निदेशक डॉ. बी.एन. सिंह, कुलसचिव डॉ. सत्येन्द्र सिंह ठाकुर तथा परीक्षा नियंत्रक डॉ.

सुनील पाटिल सहित संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 10 वर्षों से सिकल सेल एनीमिया के प्रति जनजागरूकता और स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में लगातार कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर बताया गया कि विश्वविद्यालय के 225 एनसीसी कैम्पस को सिकल सेल एनीमिया मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। ये कैम्पस समाज में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वास्थ्य संबंधी संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में उनके कार्यों की समीक्षा भी की गई। महामहिम राज्यपाल के

जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन विश्वविद्यालय से संबद्ध आयुर्वेद एवं मेडिकल साइंसेज, होम्योपैथी मेडिकल साइंसेज, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच कर आवश्यक परामर्श भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य जागरूकता, जनसेवा और छात्र सहभागिता से जुड़े विभिन्न आयोजन भी किए गए। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियानों को आगे भी जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।



डॉ. मोरेपेन गुप्त वीआईटी के 17,000 छात्रों को उपलब्ध कराएगा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं

सच संवाददाता.भोपाल

हेल्थकेयर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी डॉ. मोरेपेन गुप्त और वेल्थर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल ने एक महत्वपूर्ण समझौता कर कैम्पस में एक इंटीग्रेटेड आधुनिक हेल्थ सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। यह सुविधा वीआईटी भोपाल के 17,000 से अधिक छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इस समझौते पर डॉ. जी. विश्वनाथन, फाउंडर एवं चांसलर, वीआईटी रूप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर वीआईटी भोपाल के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. शंकर विश्वनाथन सहित डॉ. मोरेपेन गुप्त की वरिष्ठ नेतृत्व टीम भी मौजूद रही।

कैम्पस में मिलेगी व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं

इस हेल्थ सेंटर के माध्यम से कैम्पस में ही छात्रों और स्टाफ को कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनमें सामान्य चिकित्सकीय परामर्श, डे-केयर सेवाएं, नॉन-क्रिटिकल इमरजेंसी सर्जरी, पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक्स, फार्मसी सेवाएं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और वेलनेस प्रोग्राम शामिल हैं। इसके साथ ही छात्रों के लिए

स्वास्थ्य जागरूकता और लाइफस्टाइल से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं को कैम्पस तक पहुंचाने की पहल

डॉ. जी. विश्वनाथन ने इस अवसर पर कहा कि यह पहल छात्रों, शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगी। उन्होंने बताया कि वीआईटी भोपाल में देशभर से 17,000 से अधिक छात्र अध्ययन करते हैं और उनके स्वास्थ्य की देखभाल अब और अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। डॉ. मोरेपेन गुप्त ने कहा कि फाउंडर अभिषेक भयाना ने कहा कि कंपनी का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक उनके स्थान पर ही पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि यह हेल्थ सेंटर देशभर में विश्वविद्यालयों और संस्थानों में ऐसे मॉडल विस्तार की दिशा में पहला कदम है।

डायग्नोस्टिक्स और प्रिवेंटिव हेल्थ पर फोकस

डॉ. मोरेपेन गुप्त के अमृत रवि ने कहा कि कैम्पस में डायग्नोस्टिक्स और हेल्थ सेवाओं की उपलब्धता से बीमारियों को समय रहते पहचान और रोकथाम संभव होगी, जिससे एक स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण विकसित होगा।



प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स के लिए देश के विभिन्न संस्थानों द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप, अवार्ड और प्रतियोगिताओं की जानकारी अब buddy4study के सहयोग से सच समाचार पर। आवेदन के लिए लिंक करें www.buddy4study.com

आईसीपीसी इंटरशिप प्रोग्राम 2025

- विवरण: आईसीपीसी इंटरशिप प्रोग्राम 2025, पॉलिटी, पॉलिटेक्निक एंड गवर्नर्स फाउंडेशन द्वारा अंतिम वर्ष या पूर्व-अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। यह इंटरशिप कार्यक्रम युवा, उत्साही व्यक्तियों को राजनीतिक और नीति निर्माण विद्यार्थियों को एक अनुभव से अलग करता है।
- मानदंड: आवेदन अंतिम वर्ष या पूर्व-अंतिम वर्ष के स्नातक अध्ययनरत छात्रों के लिए जारी है। उन्हें स्नातक अध्ययन पूर्ण करने के बाद राजनीतिक या नीति रणनीति परामर्श में करियर बनाने में रुचि होनी चाहिए।
- इनाम/लाभ: रुपये 5,000 का मासिक स्टिपेंड तथा सहानुभूति प्रमाण पत्र।
- अंतिम तिथि: पूरे वर्ष आवेदन आमंत्रित है।
- आवेदन कैसे करें: केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य
- आवेदन लिंक: www.b4s.in/sach/ICPI1
- QR Code: <https://d4e9eg0t05513.cloudfront.net/static/images/scho-media/icpc-internship-programme-20251774330906.png>

नेशनल फेलोशिप स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स (एनएफएससी) 2026

- विवरण: नेशनल फेलोशिप स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स (एनएफएससी) 2026, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जा रहा एक अवसर है। यह फेलोशिप यूजीसी-मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षान, मानसिकी, वा सामाजिक विज्ञान संकायों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र छात्रों को प्रत्येक वर्ष 2,000 नई फेलोशिप प्रदान की जाती है।
- मानदंड: सक्षमि तब तक सरकारी द्वारा सूचीबद्ध अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए आवेदन जारी है। आवेदकों को यूजीसी-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों में पूर्णकालिक, नियमित एम.फिल. या पीएच.डी. कार्यक्रमों में नामांकित होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उन्हें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या स्नातक अभियंत्रिकी प्रवेश परीक्षा (गेट) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- इनाम/लाभ: प्रति माह अधिकतम 35,000 रुपये तथा अन्य लाभ।
- अंतिम तिथि: 20-12-2026
- आवेदन कैसे करें: यूजीसी-नेट-जेआरएफ या यूजीसी-सीएसआईआर नेट-जेआरएफ परीक्षा के मेरिट आधारित चयन द्वारा ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य।
- आवेदन लिंक: www.b4s.in/sach/NFSC1
- QR Code: <https://d4e9eg0t05513.cloudfront.net/static/images/scho-media/national-fellowship-scheme-for-scheduled-caste-students-nfsc-20261769489377.png>

नोकिया फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2026

- विवरण: नोकिया फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2026, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) या सक्षमि तब तक छात्रों में पीएचडी प्राप्त कर रहे छात्रों को नोकिया फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। यह डॉक्टरेट उम्मीदवारों को अपनी शोध कार्य को चुल्लता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखता है।
- मानदंड: आवेदन फिनिश विश्वविद्यालय में आईसीटी या सक्षमि तब तक छात्रों में डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए जारी है। आवेदकों के पास आवेदन के समय डॉक्टरेट शोध प्रबंध से सम्बंधित कम से कम एक स्वीकृत प्रकाशन होना अनिवार्य है, तथा उच्च गुणवत्ता युक्त, तीव्र गति के साइबर डॉक्टरेट अध्ययन का अक्षा रिजॉर्ड होना आवश्यक है। उन्हें पूर्व में यह स्कॉलरशिप प्राप्त न हुई हो।
- इनाम/लाभ: रु 7,500 तक की स्कॉलरशिप राशि।
- अंतिम तिथि: 15-09-2026
- आवेदन कैसे करें: केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य
- आवेदन लिंक: [/www.b4s.in/sach/NKSP2](http://www.b4s.in/sach/NKSP2)
- QR Code: <https://d4e9eg0t05513.cloudfront.net/static/images/scho-media/nokia-foundation-scholarship-20261773726760.png>

न्यूटेनिक्स नेक्स्टजेन इन्वोवेटर्स स्कॉलरशिप 2026

- विवरण: न्यूटेनिक्स नेक्स्टजेन इन्वोवेटर्स स्कॉलरशिप 2026, निर्दिष्ट विषयों एवं संस्थानों में पूर्वस्नातक छात्रों को न्यूटेनिक्स द्वारा प्रदान किया जा रहा है। यह वैश्विक पहल कम्प्यूटर साइंस या सक्षमि तब तक छात्रों में डिग्री प्राप्त कर रहे तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के स्नातक छात्रों को सहयोग एवं प्रेरणा प्रदान करती है।
- मानदंड: आवेदन भारतीय निवासियों के लिए जारी है, जो नवाचार, समावेशन एवं निरंतर सीखने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्हें प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने में एआई की भूमिका के प्रति जिज्ञासा प्रदर्शित करना अनिवार्य है। आवेदकों को निर्दिष्ट विषयों में पूर्णकालिक पूर्वस्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना एवं तृतीय या चतुर्थ वर्ष में प्रवेश करना आवश्यक है।
- इनाम/लाभ: रुपये 2,500 की स्कॉलरशिप राशि।
- अंतिम तिथि: 31-05-2026
- आवेदन कैसे करें: केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य
- आवेदन लिंक: www.b4s.in/sach/NINS1
- QR Code: <https://d4e9eg0t05513.cloudfront.net/static/images/scho-media/nutanix-nextgen-innovators-scholarship-20261773726764.png>

यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम इंडिया चांसलर्स स्कॉलरशिप्स 2026-27

- विवरण: यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम इंडिया चांसलर्स स्कॉलरशिप्स 2026-27, बर्मिंघम विश्वविद्यालय द्वारा भारत अधिवासी (ओभिसाइल्स) उन छात्रों को प्रदान की जा रही है, जिन्होंने विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु आवेदन किया है।
- मानदंड: आवेदन उन सभी भारतीय छात्रों के लिए जारी है, जिन्हें सितंबर 2026 सत्र हेतु बर्मिंघम विश्वविद्यालय के यूके कैंपस में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए प्रवेश प्रस्ताव प्राप्त हो। आवेदकों को अपने प्रस्ताव में निर्दिष्ट शैक्षणिक रकॉर्ड को पूर्ण करना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें विदेशी मुद्रा भुगतानकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए तथा उन्हें छात्रवृत्ति द्वारा कवर न होने वाले शेष मुद्रा का भुगतान करने की क्षमता होनी आवश्यक है। उन्हें संबंधित समय-सीमा तक जमा राशि और कुल मुद्रा का भुगतान करना अनिवार्य है तथा रहने के खर्च और अन्य संबंधित खर्चों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए।
- इनाम/लाभ: शिक्षण शुल्क हेतु रुपये 10,000 की छात्रवृत्ति।
- अंतिम तिथि: 31-05-2026
- आवेदन कैसे करें: केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य
- आवेदन लिंक: www.b4s.in/sach/UCBD2

बाबूलाल गौर की जयंती पर मुख्यमंत्री, मंत्रीगण ने दी श्रद्धांजलि



भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर के जन्म दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री कृष्णा गौर, कैलाश विजयवर्मा, नेता प्रतिपक्ष, विधायकगण रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी सहित विधानसभा के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होंगे। कार्यक्रम में स्वर्गीय बाबूलाल गौर के सार्वजनिक जीवन, उनके योगदान और जनसेवा से जुड़े कार्यों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी मौजूद रहे।

टिवशा शर्मा मौत मामला ॥ रिमांड खत्म, पति समर्थ और सास गिरिबाला ने आरोपों से किया इनकार

सच संवाददाता ॥ भोपाल

राजधानी का बहुचर्चित और हाईप्रोफाइल त्विषा शर्मा दहेज मृत्यु मामले में आज का दिन जांच और कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं में आरोपी बनाई गई सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और त्विषा शर्मा के पति एवं अधिवक्ता समर्थ सिंह को पांच दिन की सीबीआई रिमांड आज दोपहर दो बजे समाप्त हो रही है। सीबीआई दोनों आरोपियों को विशेष अदालत में पेश कर तीन दिन की अतिरिक्त रिमांड मांगने की तैयारी कर रही है। वहीं आरोपी पक्ष के वकील इस बार रिमांड बढ़ाने का पुरजोर विरोध करने की रणनीति बना चुके हैं। सीबीआई पिछले पांच दिनों से गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से लगातार पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी का मानना है कि मामले के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर अभी और पूछताछ की आवश्यकता है। इसी कारण सीबीआई दोनों आरोपियों को भोपाल की विशेष अदालत में पेश



कर तीन दिन की अतिरिक्त रिमांड मांग सकती है। हालांकि बचाव पक्ष भी इस बार पूरी तैयारी के साथ अदालत में उतरेगा और रिमांड बढ़ाने का विरोध करेगा। सीबीआई द्वारा मामले की गहन जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के बयानों का मिलान किया जा रहा है। बीते दिन घटना स्थल का रीक्रिएशन भी कराया गया, जिसमें पूरे घटनाक्रम को दोबारा समझने का प्रयास किया गया। जांच एजेंसी अब जब्त किए गए सभी साक्ष्यों का फॉरेंसिक परीक्षण करा रही है, जिससे मामले की दिशा और स्पष्ट हो सके। इसी बीच जांच में एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, घटनास्थल से बरामद लिंगोचर बेल्ट, जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मानी जा रही है, उसे समय पर फॉरेंसिक साइंस लैब में जमा नहीं कराया गया। आरोप है कि संबंधित सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने इसे करीब दो दिन तक अपनी कार में रखा, जिसके बाद हंगामे के बाद उसे एफएसएल भेजा गया। इस गंभीर लापरवाही के बाद सीबीआई अब संबंधित अधिकारी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने की तैयारी में है। साथ ही केस से जुड़े अन्य लोगों को भी तलब किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मेहनत-मशक्कत कर 2 जून की रोटी जुटा रहे कारीगर, पसीने में छिपी रोजी-रोटी की कहानी

सच संवाददाता ॥ भोपाल

आज 2 जून है और शहर की तेज रफतार जिंदगी के बीच ऐसे हजारों कारीगर हैं जो दिन-रात मेहनत कर अपने परिवार के लिए दो जून की रोटी जुटाने में लगे हैं। ये वे लोग हैं जिनकी जिंदगी ईंट, पत्थर, लोहे, कपड़े और औजारों के बीच बीती है, लेकिन अक्सर उनकी मेहनत सुर्खियों से दूर रह जाती है। सुबह से ही काम की तलाश में निकल पड़ने वाले ये कारीगर निर्माण स्थलों, छोटी दुकानों और वर्कशॉप्स में अपनी रोजी-रोटी के लिए श्रम करते हैं। बढ़ती महंगाई और अनिश्चित काम के बीच भी ये लोग अपने परिवार को जिम्मेदारियों को निभाने में जुटे रहते हैं। कारीगरों का कहना है कि काम मिलने पर ही घर चलता है, और कई बार दिन भर की मेहनत के बावजूद पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल पाती। इसके बावजूद वे उम्मीद नहीं छोड़ते और हर नए दिन को एक नए अवसर की तरह देखते हैं। लोगों का मानना है कि इन मेहनतकश हाथों



के बिना शहर की रफतार थम जाएगी, लेकिन इनके जीवन की चुनौतियां अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि कारीगरों के लिए रोजगार की स्थिरता, उचित मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत किया जाए। इनकी जिंदगी भले ही साधारण दिखे, लेकिन इनकी मेहनत ही शहरों और समाज की असली नींव है।

अवैध उत्खनन कर्ताओं को खुलेआम संरक्षण स्वच्छता अभियान मिशन को पलीता लगा रहा खनिज विभाग

सच संवाददाता ॥ भोपाल

जिला खनिज विभाग शासन की पवित्र योजना स्वच्छता अभियान मिशन को पलीता लगा रहा है। सफाई के नाम पर वह पंचायत में मिट्टी और मुरम अवैध रूप से बेच रहे हैं। खनिज विभाग की शह पर और पंचायत की सहमति से सफाई हो या ना हो वहां से अवैध कारोबार जारी है। इन घटनाओं से वरिष्ठ अधिकारी भी अवगत हो चुके हैं और उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। संपूर्ण जिले में खनिज माफिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अवैध उत्खनन कर रहे हैं, शासन की पवित्र योजना स्वच्छता मिशन में रास्ते में जो जंगल झाड़ी और

अविरुद्ध रास्ते को साफ करने के लिए पंचायत को निर्देशित किया गया है कि वह सफाई करें। शासन के इस आदेश का पालन पंचायत और खनिज विभाग कुछ इस तरह कर रहे हैं कि वह रास्ते में जहां अच्छी मिट्टी है उसकी गहरी गड्ढों में तब्दील कर रहे हैं और जहां पर मुरम है जिसकी रॉयल्टी देना आवश्यक है उसको भरकर बेचा जा रहा है। पूरे जिले से हर जगह इसी प्रकार की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसमें खनिज विभाग पंचायत और ठेकेदारों के बीच बहुत बड़ी साझेदारी है और सब मिलकर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इसके अलावा शासकीय भूमि चाहे वह पट्टे वाली शासकीय जमीन हो या फिर वन/विभाग, मरघट,

शमशान और शासकीय परिधि में आने वाली जमीन हो वहां से उत्खनन किया जा रहा है जिसकी निरंतर शिकायतकमिशनर, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, को मिल रही हैं और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संबंध में खनिज विभाग के अमले पर नाराजगी व्यक्त की है। मगर होता यह है कि इसी लोगों की शिकायत होती है तो जांच अधिकारी भी यही लोग होते हैं, और स्वयं अपने पक्ष में पंचनामा बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह कर देते हैं। इसके अलावा एक बात और है कि खनिज विभाग के लोग पंचायत को ब्लैकमेल करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को फरमान सुनाते हैं।

ग्रेविटी पाइपलाइन में मरम्मत कार्य से 36 घंटे का वॉटर शटडाउन

सच संवाददाता. भोपाल

राजधानी भोपाल में जल संकट की स्थिति बनने वाली है, क्योंकि नगर निगम ने कोलार जलप्रदाय परियोजना की मुख्य ग्रेविटी पाइपलाइन में मरम्मत कार्य के चलते 36 घंटे का वॉटर शटडाउन घोषित किया है। यह शटडाउन आज सुबह 10 बजे से बुधवार सुबह 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। भोपाल नगर निगम के अनुसार यह मरम्मत कार्य जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और स्थायी बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस दौरान पाइपलाइन पूरी तरह बंद रहेगी और मरम्मत कार्य देर रात तक जारी रहने की संभावना है। शटडाउन के कारण शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। इनमें शाहजहाँनबाद, शाहपुरा, अररा कॉलोनी, शिवाजी नगर, चार

प्रदेश में चरणबद्ध रूप से शुरू होगी परिवहन सेवा रक्षाबंधन पर बहनें करेंगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन की बसों में सफर: माहन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य परिवहन सामान्य जन के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राज्य सरकार न सिर्फ प्रदेश में बेहतर और आधुनिक सड़कों का नेटो से निर्माण कर रही है, बल्कि जल्द ही नागरिकों को राज्य परिवहन की विशेष सुविधा भी देने जा रही है। राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री



सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की ओर बढ़ रही है। इस बार रक्षाबंधन पर हमारी बहनें परिवहन

विभाग की बसों में सफर करें, इसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यह जानकारी विधानसभा में मौडिया से चर्चा में दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के कारण शहरों के बीच दूरी अधिक है। बसें उपलब्ध नहीं होने पर लोगों को मजबूरी में लोंडिंग गाड़ियों में सफर करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा इन सभी समस्याओं को खत्म करेगी। उम्मीद है कि राज्य के अंदरूनी हिस्सों और पड़ोसी राज्यों के साथ मध्यप्रदेश सरकार का यह प्रयास सुगम परिवहन सेवा के रूप में देखने को मिलेगा। प्रदेश में जनसुविधाओं के विस्तार और प्रदेश के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

कोलार और टीन शेड स्थित शराब की दुकान पर हुई कार्रवाई नियमों को धता बताकर शराब की बिकवाली बढ़ाने फ्री दिए जा रहे ग्लास और पाउच

सच संवाददाता ॥ भोपाल

आबकारी नियमों के अनुसार लाइसेंसी दुकानों से केवल और केवल वह शराब ही बेची जा सकती है जिसकी अनुमति मिली हुई है। कोलार और टीन शेड की दुकानों में इस नियम का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। बीती रात आबकारी विभाग की टीम ने सूचना मिलने के बाद कोलार इलाके की शराब की दुकान पर छापेमारी की। यहां से बड़ी मात्रा में पानी के पाउच और ग्लास जब्त किए गए हैं। टीन शेड स्थित एक दुकान पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है।



जानकारी यह भी थी ग्राहकों की मांग पर उन्हें चखना भी दिख जाता है। इस तरह की सूचनाएं कई दिनों से आने के बाद आबकारी विभाग की टीम ने बीती रात कोलार की शराब की दुकान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान यहां पर दुकान के स्टोर रूम में पानी के पाउच से भरी हुई बोरी मिली जबकि प्लास्टिक के ग्लास का पैकेट काउंटर पर ही छिपाकर रखा गया था। आबकारी अधिकारियों का मानना है कि इतनी अधिक मात्रा में ग्लास और पाउच दुकान के ठेकेदार की अनुमति के



बगैर नहीं रखे जा सकते हैं। टीम ने ग्लास और पानी के पाउच की बोरी को जब्त कर लिया है। साथ ही दुकान के ठेकेदार और कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है अगर आगे से इस तरह से शराब के साथ फ्री सामग्री बेचने की शिकायत दोबारा मिली तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोलार की तरह ही टीन शेड की दुकान भी इसी तरह की कार्रवाई हो चुकी है। यहां पर शराब की बिक्री को बढ़ाने के लिए फ्री सामान देने वाली स्कीम चलवाई जा रही थी।

रानी कमलापति-संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस के निरस्त किए गए फेरे बहाल

10 जून से खुलेंगे स्कूल, कक्षाएं 16 जून से संचालित

भोपाल। मध्य प्रदेश में गर्मी की छुट्टियों के बाद नए शैक्षणिक सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के अलग-अलग बोर्ड और स्कूलों में कक्षाओं की शुरुआत अलग-अलग तारीखों पर होगी, जबकि शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सीबीएसई बोर्ड के तहत आने वाले स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 10 जून से शुरू हो रहा है, जबकि कक्षाएं 16 जून से नियमित रूप से संचालित होंगी। वहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन (केंद्रीय विद्यालय संगठन) के स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति 22 जून से शुरू होगी। प्रदेश के निजी स्कूल भी राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कक्षाएं संचालित करेंगे। सहोदय ग्रुप के अनुसार अधिकांश प्राइवेट स्कूल प्रशासनिक तैयारियों के लिए कक्षाएं शुरू करने से पहले लगभग छह दिन का समय लेंगे।

भोपाल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में बिलासपुर जंक्शन-चापा जंक्शन रेलखंड पर चला रहे अद्योत्सवकार्यक्रम कार्यों के कारण पूर्व में प्रस्तावित प्री-नॉन इंटरलॉकिंग एवं पोस्ट नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों को अब निरस्त कर दिया गया है। इस बदलाव के चलते पहले जिन ट्रेनों के फेरे अस्थायी रूप से रद्द किए गए थे, उन्हें अब बहाल कर दिया गया है। इस निर्णय के तहत भोपाल मंडल से प्रारंभ/समाप्त होने वाली संतरागाछी-रानी कमलापति-संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस अब अपने नियमित कार्यक्रम के अनुसार सामान्य रूप से संचालित होगी।

पेसा मोबिलाइजरों की सेवा समाप्ति के खिलाफ धरना, बहाली और स्थायी नीति की मांग

सच संवाददाता ॥ भोपाल

मध्यप्रदेश में पंचायत पेसा मोबिलाइजरों की सेवा समाप्ति को लेकर विवाद तेज हो गया है। पंचायत पेसा मोबिलाइजर कर्मचारी संघ, जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है, ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आदेश को निरस्त करने और सभी कर्मचारियों की बहाली की मांग की है। संघ ने आरोप लगाया है कि पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्रमांक 8448 के तहत प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत पेसा मोबिलाइजरों को एकतरफा तरीके से सेवा से मुक्त किया गया है, जो उनके अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। संघ के अनुसार पेसा मोबिलाइजर वर्षों से ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने, पेसा अधिनियम



के प्रचार-प्रसार, योजनाओं के क्रियान्वयन, सामाजिक विवादों के समाधान, शराबबंदी और जनजागरूकता जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से पांच प्रमुख मांगें रखी सेवा समाप्ति आदेश निरस्त कर बहाली, स्थायी नीति बनाकर समायोजन, मानदेय बढ़ाव, इंदौर, एरियर भुगतान, और सेवा समाप्ति

से पहले निष्पक्ष सुनवाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना। संघ का कहना है कि इस निर्णय से हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन की प्रतिलिपि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जनजातीय विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई है।

नौतपा में राहत: 45 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, मानसून में देरी की संभावना

सच संवाददाता ॥ भोपाल

राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा तपिश की बजाय आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के लिए चर्चा में है। लगातार सक्रिय प्री-मानसून सिस्टम के कारण प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और कई जिलों में तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार नौतपा के अंतिम दिन मंगलवार को भी प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी, बारिश और चलावृष्टि में ओले गिरने की संभावना बताई गई है। कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफतार से तेज हवाएं चल



सकती हैं। लगातार बारिश और बादलों के कारण दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खंडवा में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि पचमढ़ी में रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं और पश्चिमी विक्षोभ के असर से

बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि मानसून की गति इस बार कुछ धीमी है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में इसकी दस्तक सामान्य से लगभग 5 से 7 दिन देरी से हो सकती है। सामान्यतः मानसून 15 जून के आसपास आता है, लेकिन अब इसके 20 से 22 जून के बीच पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। इसी बीच राजधानी भोपाल में कोलार पाइपलाइन मरम्मत के कारण 36 घंटे के वॉटर शटडाउन की स्थिति भी बनी हुई है, जिससे शहर के कई हिस्सों में जलापूर्ति प्रभावित है।